"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted

SHRI HARINATHA MISRA : I introduce the Bill.

12.47 hrs.

Discussion or Non-implementation of the Recommendations of the Mandal Commission (Backward Classes Commission)

MR. DEPUTY SPEAKER : We will now take up discussion under Rule 193 on the non-implementation of the recommendations of the Mandal Commission (Backward Classes Commission) by Government.

I would like to remind the Members that the Hon. Speaker had announced in the House yesterday that this discussion would continue upto 3.30 p.m today. This would give 2.40 hrs. time to the Members to participate in the discussion. The participating members should see that they stick to the allotted time so that discussion is completed by 3.30 p.m. today.

The available time has been distributed among the various party groups as usual and the time given to the share or each party or group is as follows.

CPI (M) — 12 minutes, Lok Dal — 8 minutes, Janata — 7 minutes, BJP — 6 minutes, Congress (I) — 1.40, DMK — 5 minutes, CPI — 4 minutes, DSP — 3 minutes, Congress (S) — 2 minutes; Unattached — 6 minutes and the total time for other small parties — 8 minutes

The Hon. Members may kindly ensure that they complete their remarks witnin the allotted time. Not even a second can be wasted now.

(*Interruptions*)

SHRI RAMAVTAR SHASTRI (Patna) : At least 10 minutes should be given to each member.

MR. DEPUTY SPEAKER : The mover will get 15 minutes. It is not a question of members speaking alone. But it is a question of the reply of the Government also.

I may inform the Hon. Members that there is no Lunch Hour today. But you can have your lunch.

Shri Ram Vilas Paswan

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : इस सदन में मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर हम दुबारा बहस कर रहे है । इस बार हम लोगों के बीच में गृह मंत्री के रूप में सेठी साहब हैं । मुझे उम्मीद है कि जब वे जवाब देंगे तो हिन्दुस्तान की बहुसंख्यक जनता जो बहुत ही जोर से इस डिबेट का उत्तर जानने के लिए उत्सुक है, निश्चित रूप से निराश नहीं करेंगे । पिछली बार इस रिपोर्ट पर काफी चर्चा हुई थी उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता हूं । पिछली चर्चा में जो बात नहीं आई उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

आयोग दो तरह के होते हैं, प्रशासनिक और कांस्टीट्यूशनल । जहां तक मंडल कमीशन का सम्बन्ध है, वह कांस्टीट्यूशनल था तथा संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत उसका निर्माण किया गया था । संविधान की धारा 340 में लिखा हुआ है ।

"340 (1) The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and

to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any State and the conditions subject to which such grants should be made and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission."

इसी धारा के सब सेक्शन तीन में यह कहा गया है :-

"(3) The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each House of Parliament."

इस उप धारा में 'मैं' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि 'शैल' शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां सरकार के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है।

340 जो पहले 301 धारा थी इस पर जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो उसको मैंने देखा है। 301 आर्टिकल पर पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बहस शुरू की थी और अपने भाषण में उन्होंने साफ कहा था :

"I consider that article 301—that is new 340—is one of the most important articles of the Constitution. I would call it the soul of the Constitution. It is really a charter of the liberties of the backward classes."

".....In a sense this is an oath taken by the House, an oath to see that within the coming years, we will provide all facilities which can be provided by the nation for expiating our past sins."

"I would, therefore, have liked a register to be made for all the backward classes including the present Depressed Classes."

"If any community continues in backwardness, socially, culturally or educationally, then, it should not be a question of 10 years or 15 years but up to the time they are brought up to normal standards, facilities should be given and continued for them."

यह संविधान निर्माता कांस्टीटुएन्ट असेम्बली के लोगों का विचार है। उन्होंने कहा कि—

"Even though the word 'may' has been used, it must be construed as 'shall'."

"The only responsibility of the Parliament are the Scheduled Castes and the backward classes."

बैकवर्ड क्लासीस का मामला है, पार्लियामेंट की सीधी लायेब्लिटी है।

प्रो० सिब्बन लाल सक्सेना ने कहा कि—

" In regard to these classes, Special Officers are to be appointed to see whether the fundamental rights which have been given them under the Constitution and the special facilities wihch are sought to be provided for them after the investigation of the Commission, are enjoyed by these people or not."

इसमें इकनामिकली कहीं किसी ने नहीं कहा है।

PROF. SIBBANLAL SAXENA :

".....As soon as our Constitution comes into existence, the President shall appoint the Commission to investigate into the conditions of the socially, educationally and culturally backward classes."

"and then make its report on how to remove their backwardness."

"We are using the expression the "backward classes" in several places in the Constitution but we have not defined them any where in the whole Constitution. I hope this Commission which will specially investigate the conditions of the backward classes all over the country will be able to tell us what is meant by the term 'backward classes'. When the Commission reports to the Parliament, I hope they will define the terms 'backward classes' and the 'depressed classes' in their report."

सरकार अब कहती है कि बैकवर्ड क्लासीस कौन हैं उसका विवरण मैं स्टेट गवर्नमेंट से मांग रहा हूं। मैं कहता हूं कि संविधान के निर्माता एमीनेन्ट लोग थे, राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने इस बात को साफ-साफ कहा, जब पिछली बार मैंने इस मामले को उठाया था और श्री वैंकटसुब्बय्या जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन इस सदन में दिया था, क्योंकि जब उन्होंने हाउस में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 30 अप्रैल, 1982 को पेश किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि मैंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट भी रखी है। उसी समय मैंने एक प्रस्ताव दिया था और ओबजेक्शन किया था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं दी है।

उसके बाद काफी हंगामा इस सदन में हुआ। फिर मंत्री महोदय ने कहा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट दी गई है और एक्शन टेकन रिपोर्ट के नाम से मैंने स्टेट गवर्नमेंट्स से ओपीनियन मांगी है। मंडल कमीशन की दो मोटी-मोटी किताबें हैं, इनमें आप जाइये, मंडल कमीशन ने हिन्दुस्तान की जितनी भी सोसाइटीज के लोग थे, इन्टलेक्चुअल, प्रोफेसर, पालीटीशियन या समाज के किसी भी तबके के लोग थे, सबसे उन्होंने सम्पर्क स्थापित करने का काम किया और उन्होंने सबके नजदीक जाकर यह मोटी किताबें आपके समक्ष रखी हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स से क्या राय मांगी जा रही है ?

कांस्टीट्युन्ट असेम्बली में श्री एस. नागप्पा ने कहा था यह कार्यवाही के पेज 657 पर लिखा है :—

"I think you are aware that, as a result of the hard labour and struggle under the leadership of Mahatma Gandhi, the country has become free politically. But this particular section of the population is doubly free in that it is not only politically free but it is also socially free....."

"Freedom means political, social and economic freedom. Two aspects of freedom. have been covered by this particular amedment, thanks to the efforts of Gandhiji who has brought about such a social renvolution."

आगे चल कर नागप्पा साहब कहते है :—

"Most of our courts are courts of law and not justice. One should be more correct in framing the clause."

संविधान के निर्माताओं ने उस समय भी डाउट किया था कि इसका क्या हश्र होने वाला है।

आखिर में एक मेम्बर ने कहा था :

"I hope that the Hindu society will realise that they have now to change those habits and that anybody who is not a Hindu will be able to....."

सरकार ने सबसे पहली गलती यह की कि एक्शन टेकन रिपोर्ट के रूप में उसको जो काम करना चाहिए था, वह उसने नहीं किया

सरकार को इसे मान लेना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं माना ।

कल और आज भी इस सदन में चर्चा हुई कि हिन्दुस्तान एक बैकवर्ड राष्ट्र है, डेवेलपिंग कन्ट्री है और डेवेलप्ड कन्ट्रीज हमारा शोषण कर रहे हैं, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाए हमें लोन या सहायता नहीं देती हैं । बैकवर्ड राष्ट्र होने के नाम पर हम सब प्रकार की सहायता लेना चाहते हैं देश के अन्दर यह कहा जाता है कि बैकवर्ड स्टेट्स को विशेष सुविधाएं, स्पेशल फैसिलिटीज दी जाएं । लेकिन देश में जो सोसायटी बैकवर्ड है, वहां उस सिद्धान्त का पालन क्यों नहीं होता है ?

कई लोग कहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों में एफिशेंसी नहीं है और समानता का सिद्धान्त क्यों नहीं लागू किया जाता है । मंडल कमीशन ने बताया है :-

"1892 और 1 04 के बीच में भारतीय सिविल सेवाओं में सफलता प्राप्त करने वाले 16 उम्मीदवारों में से 15 ब्राह्मण थे । 1914 में 123 स्थायी जिला मुंसिफों में से 93 ब्राह्मण थे । 1944 में विश्वविद्यालय के 650 पंजीकृत स्नातकों में से 452 ब्राह्मण थे ।"

मेरा उद्देश्य ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज करना नहीं है । तथ्य यह है कि जो सोसायटी जितनी डेवेलप्ड होती है, उतना ही अधिक उसको फायदा होता है । जिसके पास शुरू से ही अधिकार और प्रिविलेज रहे हैं, जो प्रिविलेज्ड क्लास है, स्वभावत: उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है । मैं आज की जेनरेशन के ऊंची जाति के लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं । लेकिन जिन लोगों को हजारों सालों से दबा कर रखा गया है, उनको दूसरों के समक्ष लाने के लिए व्यवस्था करनी होगी ।

मंडल कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है-:

"मद्रास के ताड़ी का काम करने वाले शोनार से एक ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है, यदि वह ब्राह्मण से केवल 24 कदम दूर है ।··· कोई नायर किसी नम्बूदरी ब्राह्मण के पास तो जा सकता है किन्तु वह उसे छू नहीं सकता, जबकि एक तियान को चाहिए कि वह स्वयं को एक ब्राह्मण से 36 कदम की दूरी पर रखे और कोई पुलयान उससे 96 कदमों की दूरी पर रखे । एक तियान किसी नायर से 12 कदम दूर रहे । चाहे कुछ जातियां तियान के पास तो जा सकती है, किन्तु वे उसे छू नहीं सकती हैं ।"

13.00 hrs.

श्री चन्द्रभालमणि तिवारी : क्या यह रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती है ।

MR. DEPUTY SPEAKER : There is no time. He is the first speaker. You will all have your chance. When you have it, you will either oppose it or support it.

13.01 hrs.

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*]

श्री रामविलास पासवान : रिपोर्ट के पेज 14 पर लिखा है—मराठा देश में एक महार-अछूतों में से एक सड़क पर नहीं थूकेगा, क्योंकि यदि किसी सवर्ण हिन्दू के पांव इससे छू जायेंगे तो वह अपवित्र हो जाएगा, लेकिन उसे चाहिए कि वह अपने गले में लटकता हुआ एक मिट्टी का बर्तन रखे, जिसमें वह थूके । इसके अलावा

अपने पैरों के निशानों को मिटाने के लिए वह अपने पास एक कांटेदार डाली रखे और यदि कोई ब्राहमण नजदीक से गुजरे तो कुछ दूरी पर दंडवत लेट जाये, ताकि उसकी गन्दी परछाई से पवित्र ब्राहमण भ्रष्ट न हो जाये ।

इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है--तिन्नोवली जिले में न देखें जाने वाली एक जाति है, जो पुरादा बन्नान कहलाती है । उन्हें दिन के समय बाहर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनका दिखाई देना अपवित्र समझा जाता है । यह स्थिति आज भी है । ४० साल की आजादी के बाद भी एक जाति विशेष को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उसका दिखाई देना अपावेत्र समझा जाता है । इन लोगों में से कुछ को जो अन्य बाहरी जातियों के कपड़े अर्ध रात्रि से पौ फटने तक धोते हैं, साक्षात्कार के लिए घर से बाहर निकालने हेतु राजी करने में कठिनाई पेश आई ।

MR. CHAIRMAN : How much time will you take ?

SHRI RAM VILAS PASWAN : I shall take 15 mintues.

MR. CHAIRMAN : Please conclude in two or three minutes.

श्री राम विलास पासवान : मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हू क्यों कि मंडल कमीशन ने पूरा काम किया है । सजा के बारे में बात करते हैं, मैंने इसी सदन में कहा था अंग्रेज़ों के समय में कानून के सामने सबको बराबर का अधिकार दिया जाता था । जिसके लिए आज भी सेठी जी से हम लोग मांग करते है । कलियुग को छोड़ कर कौन से युग में कानून में सबको बराबर का अधिकार था ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : बिल्कुल था ।

श्री राम विलास पासवान : बिल्कुल नहीं था । कहा जाता है कि करों का लगाना भी किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है । "एक ब्राह्मण को आम करों से छूट थी । ब्राह्मण स्वयं तथा सम्पत्ति की दृष्टि से बिल्कुल अदूषित माने जाते थे । ··· (**व्यवधान**) ··· सभापति जी, मैं कह रहा था कि हजारों सालों से आपने किसी जाति विशेष को बांध कर रखा है और आज आप कहते है कि समान प्रतियोगिता में जाओ । समानता किसके बीच में ? समानता लाने के लिए आपको वैसा ही इन्वार्यनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ।

श्री चन्द्रभालमणि तिवारी : पासवान जी आप यह वाक्य वापिस ले लीजिए । तुलसी दास जी ने कहा था—

सिया राम मय सब जग जानी,
करहू प्रणाम जोरि जुग पानि ।···

(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN : This is a very important report which is only discussed in this House. I would request the Hon. Members not to interrupt him. Please allow him to continue. Mr. Paswan, you will now please conclude.

श्री राम विलास पासवान : मैं आपको 1982-83 की आई.ए.एस. रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं । ब्राह्मण की जनसंख्या 5.52% राजपूत 3.90% मराठा 2.27% और जाट 1% पूरे देश की ही और 1982-83 का जो आइ.ए.एस. का रिज्लट निकला उसमें कुलसंख्या 963, जिनमें से ब्राह्मण 309, उच्च जाति 499 और पिछड़ी जाति के केवल 26 लोग थे ।

श्री चन्द्रभालमणि तिवारी (बलरामपुर) : यह उनके ब्रेन की बात है ।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैं ब्रेन के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं । यदि ब्रेन पर आ जाएं तो हम लोग जो यहां बैठे हैं एक-आध आदमी को छोड़ कर सब रिजेक्टेड हैं । पी०एच०डी० वाले सब बाहर हैं, देश चलाने के लिये आप बैठे हैं । आप कितने पी०एच०डी० हैं, हमको मालूम है·····

MR. CHAIRMAN : Please don't interrupt.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उनको ये बर्डस वापस करने चाहिये । क्या सब मूर्ख हैं ? क्या यह कास्टिज्म नहीं है ? इनके दिमाग में खुद कास्टिज्म हैं·····

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : सभापति महोदय, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में विस्तृत रूप से चर्चा की है·····

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : वह अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं उनका क्यों इस तरह से विरोध कर रहे हो ? जो कमजोरी है उसको दुरुस्त करो, उनको बोलने दो ।

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

श्री रामविलास पासवान : सभापति जी, यह आपकी डयूटी है, आप इनको रोकिये । यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट है जिसकी मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं । मैं यही बतला रहा हूं कि मंडल कमीशन ने क्या कहा है । मंडल कमीशन कहता है — केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में बैकवर्ड क्लासेज की क्या स्थिति है ।

मंत्रालय	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या	इनमें बैकवर्ड क्लासेज के अधिकारियों की संख्या
1 2	3	4
1. राष्ट्रपति सचिवालय	49	एक भी नहीं
2. उपराष्ट्रपति सचिवालय	7	एक भी नहीं
3. प्रधानमंत्री कार्यालय	35	1
4. मंत्रीमंडल सचिवालय	20	1
5. कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय	261	13
6. परमाणु ऊर्जा	34	एक भी नहीं
7. नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता	61	एक भी नहीं
8. संचार	52	एक भी नहीं

1	2	3	4
9.	रक्षा	1379	9
10.	शिक्षा एवं समाज कल्याण	259	4
11.	इलेक्ट्रोनिक्स	92	2
12.	ऊर्जा	641	20
13.	विदेश मंत्रालय	649	1
14.	वित्त मंत्रालय	1008	1
15.	स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण	240	एक भी नहीं
16.	गृह मंत्रालय	409	13
17.	उद्योग मंत्रालय	169	3
18.	सूचना तथा प्रसारण	2506	124
19.	विधि कार्य	143	5
20.	विधायी कार्य	112	2
21.	कम्पनी कार्य	247	6
22.	श्रम	74	एक भी नहीं
23.	संसदीय कार्य	18	एक भी नहीं
24.	पैट्रोलियम तथा रसायन	121	एक भी नहीं
25.	योजना	1262	72
26.	विज्ञान और प्राद्योगिकी	101	1
27.	जाहजरानी और परिवहन	103	1

इसलिये मैं कहता हूं···

प्रो० मधु दण्डवते (Rajapur : कैबिनेट में सारे ही पोलिटीकली बैकवर्ड हैं ।

श्री रामविलास पासवान : इसीलिये मैंने कहा है कि हजारों सालों से नीचे करके रखा है - आप इस थोड़ा गम्भीरता से सोचिये, इसके बारे में जो पहला संविधान संशोधन हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं । कांग्रेस वाले यहां पर बहुत कुछ चिल्ला रहे हैं और वे जवाहरलाल नेहरु जी का नाम लेते हैं । मैं उनका कोटेशन पढ़ कर सुनाता हूं । प्रथम जो संविधान का संशोधन हुआ था वह इसी इशू पर हुआ था और हिन्दुस्तान को आजाद हुए तब 16 महीने ही हुए थे । जो संशोधन लाया गया था, वह आर्टीकल 15 पर लाया गया था और जब वह संशोधन लाया गया था, उस वक्त भी कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था और

यह कहा था कि आप संविधान की धज्जियां क्यों उड़ा रहे है। सभापति महोदय, पं० जवाहरलाल नेहरु ने उस समय संशोधन पेश करते हुए जो कहा था, उसका एक अंश मैं यहां पढ़ कर सुनाना चाहता हू :

> "Without going into the details of this article or of the amendment proposed, I wish to say a few words about—shall I say—our basic ideas on this subject. Why have we done this and wny has it been thought that these articles come in the way of doing something that we wish to do ? The House knows very well and there is no need for trying to hush it up, that this particular matter to this particular shape arose because of certain happenings in Madras. Because the Government of the State of Madras issued a G.O.—I do not know the details of it—by making certain reservation etc. for certain clauses of certain comments—rather for all communities—and the High Court of Madras has said that this G.O. was not in order, was against the spirit of or letter of the Constitution, etc."

लास्ट में उन्होंने कहा है क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने खिलाफ में आर्डर दिया था और पेरीयार के नेतृत्व में आन्दोलन चल रहा था।

> "We bow to the decision of the High Court of Madras in that matter, the fact remains that we have to deal with the situation where for a variety of causes for which the present generation, is not to blame; the past has the responsibilities, there are groups, clauses, individuals, communities, if you like, who are backward. They are backward in many ways, economically, socially, educationally, sometimes they are not backward in one of these respects and yet backward in another. The fact is therefore that if we wish to encourage them in regard to these matters, we have to do something special for them. We come up against this difficulty that we talk on one hand, in our Directive Principles of Policy of removing inequalities in raising people up in every way, socially, educationally, economically, reducing the distances which separate groups or clauses of individuals from each other, we cannot separate them entirely, we cannot make a fool a wise man or make a wise man a fool."

यह पं० जवाहरलाल नेहरु ने उस समय कहा था और जो लोग ट्रेजरी पेचेज पर आज बैठे हैं और जो अपने को गांधी जी के आदर्श पर चलने वाले कहते है, मैं समझता हूं कि उनको इस तरह की बात कहना शोभा नहीं देता है। इसको करना है या नही करना है, यह आप जानिये लेकिन मैं एक बात दोनों पक्षों के लोगों से कहना चाहता हूं कि वे इस बात को समझ लें कि आज सेठी साहब इस मंडल कमीशन की रिकमेडेशन्स को मानें या न मानें, आगे आने वाला इतिहास इसे लड़ कर ले लेगा और आपकी मर्जी नहीं चल पाएगी। आप तर्क देते हैं कि मंडल कमीशन ने इतनी सारी जातियों का नाम दे दिया जबकि काका कालेलकर ने कम जातियोंक नाम दिया था। मैं बताना चाहता हूं कि काका कालेलकर कमेटी ने 1931 के गजेट के मुताबिक जातियों का नाम दिया था और मंडल कमीशन गांव-गांव में घूमा है और फिर उसने जातियों का नाम दिया है। पहले यादव को एक जाति माना गया था लेकिन विभिन्न सूत्रों में इस जाति के 78 नाम हैं इसी तरह से मल्लाह के 99 नाम हैं, वढ़ई के 98, सौनी के 46, गूजर के 80 और नाई के 90 नाम जातियों के दिये हैं और मंडल कमीशन ने इतनी उदारता दिखाई है कि विभिन्न राज्यों में उसने राजपूतों को भी बैकवर्ड माना है और कहीं पर ब्राह्मणों को भी

बैकवर्ड माना है लेकिन हमारे मित्रों को रिपोर्ट को पढ़ने से दुश्मनी है। मैं आपसे कहता हूं कि आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़िये। मंडल कमीशन ने कई स्टेट्स में ब्राह्मण और राजपूत को भी बैकवर्ड माना है। इसलिए इसमें ईर्ष्या करने की यात नहीं है। कुछ लोगों को इससे ईर्ष्या है। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब अंग्रेज यहां से गये थे तो उस वक्त भी बहुत से लोगों को ईर्ष्या थी। अंग्रेज कहा करते थे कि हम लोग पुलिस इंस्पेक्टर के भी काबिल नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एफीशियेन्सी की बात को न उठायें। आज तमिलनाडु में 68 परसेंट रिजर्वेशन है और कर्नाटक में 68 परसेंट रिजर्वेशन है। आंध्रप्रदेश में रिजर्वेशन है। लेकिन ये राज्य आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों से ज्यादा अच्छा शासन कर रहे हैं।

इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर यहां 50 संसद सदस्य गिरफ्तार हुए। इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस आई सरकार नहीं चल पा रही है। जब इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर बहस होती है तो यहां भी दोनों पक्षों के लोग इसका समर्थन करते हैं। मैं ऊंची जाति के लोगों से कहता हूं कि आप बुद्ध के रास्ते को अपनाइये, दयानन्द सरस्वती के रास्ते को अपनाइये, स्वामी विवेकानन्द के रास्ते को अपनाइये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने इस विषय में क्या कहा था —

"मैं मर कर मुक्ति चाहता हूं, लेकिन मुझे अगर दुबारा जन्म लेना पड़े तो मैं किसी भंगी के यहां जन्म लेना पसंद करूंगा ताकि इस जाति का जो आज तक अपमान हुआ है, उसके बारे में मुझे अनुभव हो सके।"

जिसके पैर फटे न बिवाई,
वह क्या जाने पीर पराई।

मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि या तो सरकार मंडल कमीशन की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दे या फिर हम इन सिफारिशों को लड़ कर लागू करवायेंगे। अगर इसमें सभी पार्टियों के लोग साथ देंगे तो गांवों में हारमनी रहेगी, जातिवाद के आधार पर विभाजन नहीं होगा जैसा कि बिहार में जातिवाद के आधार पर विभाजन हुआ। यह दो जेनरेशन की लड़ाई है।

MR. CHAIRMAN : I appreciate your feelings, but you must conclude now. You asked for 25 minutes and I have given you 32 minutes.

श्री राम विलास पासवान : मैं कह रहा था कि यह अधिकार की लड़ाई है। जो आज बहुमत में है, उसको अब ज्यादा दिन तक दबा कर आप नहीं रख सकते हैं।

चौधरी सुन्दर सिंह की जेनरेशन ने बर्दाश्त कर लिया, इसे जगजीवन राम जी की जेनरेशन ने बर्दाश्त कर लिया।

श्री सुन्दर सिंह : हम भी इसे सहन नहीं करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन राम विलास और पनिका जी की जेररेशन इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। या तो आप हमें अधिकार दीजिए और आज ही इसकी आप घोषणा कीजिए, नहीं तो जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमको आप क्या धमकी देते है
हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे।

SHRI UTTAM RATHOD (Hingoli) : Mr. Chairman, Sir, when we are discussing such a scrious topic, through you, I would request...

MR. CHAIRMAN : I will join with you and request all the Hon. Members not to interrupt. A very important subject is being discussed. I would earnestly request all the Hon. Members not to interrupt. They can reply when their turn comes.

SHRI UTTAM RATHOD : Sir, last time on the 11th of August 1982 this particular Report was discusseed in this House threadbare.

I don't feel it is essential to discuss it again, as my learned friend, Mr. Ram Vilas Paswan has done. I would only say that the methodology and data base that were used by the Mandal Commission were scientific. They have derived certain conclusions which we should all accept.

Inspite of giving all arguments, all scientific arguments, it is not possible for us to convince everybody. We can convince some people who are prepared to be convinced, but we cannot convince those who do not want to be convinced, because what we say, goes against their own interests. That is why they will never agree to this.

I heard some people speaking about casteless society. Last week, we discussed Shrimati Vidya behn's resolution. Please tell me how many of us are married inter-caste ? How many of us are prepared to give our daughters or sisters in marriage, inter-caste? It is all right to speak here. But when we go to the society; it is the society's law that rules us. Let us not forget it. That is why I say it is high time you accept this Mandal Commission's report. There is no other way to get out of it. If you really want to build up this country, you cannot neglect these 52% people in this way. They have been neglected during the last 35 years. Though there was a constitutional obligation on the part of the Government, under Article 340, that certain things should be done for the upliftment of the backward classes, it was not done. Why, I do not know. But here is a chance for the Government and also for the society to do something for them which, I feel they should avail of.

Interesting things have come up after the last discussion. This world is really a wonderful thing. Just now, Mr. Paswan spoke well about the Britishers. Really they were great people; that is why they could rule us. I was reading Times of India, about 15 days back. There was a column called 'Hundred Years Back.' It said that five tribals from Andaman and Nicobar islands were brought to Calcutta, and they were lodged in the Zoo, along with animals—not in the botanical gardens, and not in any thatched house; but lodged in the zoo.

That was the state of affairs then. It may not be the same now. The degree of it might have changed.

This Mandal Commission has discussed the question in all the aspects—legal, social, educational and even economic. I think I need not go into the details of it. Their report should be accepted.

Coming to certain arguments that were advanced through the media, I have to say, that there are some people who do not want this thing to come up, because they feel that if certain reservations are introduced, they will be deprived of the privileges which they have been enjoying for centuries together. We cannot help it. The Constitution does not help them. So, I would request them to please accept the Constitution, to accept the new sense of awareness and the new emotions that have developed in the country.

Is it not a fact that in the recent past when we started with economic planning, we accepted a politic-economic terminology, viz. 'backlog' as far as economic matters are concerned ? Is it not a fact that regions of a State called Vidharba and Marathwada have this 'backog' as against the western Maharashtra or Bombay ? So, we are going ahead. We cannot remain static. Society can never remain so. We have to go ahead. For that, we have to change.

They say that reservation is out of time today. Recently, I came across some people who had the good fortune of staying in Europe for quite some time. To my utter

surprise, they told me that in Europe, in one of the Scandinavian countries, they have given certain concessions to highlanders. They also told me that even in America, the Red Indians enjoy certain concessions.

We have different castes, sub-castes. Maheshwaris do not marry Agarwals. Mr. Daga will agree with me. Is it not essential to give some concessions to the backward classes who have been neglected by the society as well as by the government ? I would only request that all the people should be magnanimous enough to accept the Mandal Commission Report and give justice to the people. The justice is not only denied by the society but also by the government to these people. Just as we have fulfilled certain other constitutional obligations in other cases, let us fulfil this constitutional obligation under 340, which gives certain benefits to the backward classes.

I would like to tell something to those who do not agree with me. Of course, they have every right to disagree with me. When they speak about equality, I am reminded of the great English writer, George Orwell. It is a famous fairy tale—ANIMAL FARM. I think most of you must have read it. He says, "All animals are equal but some are more equal than others." This cannot continue.

With these words, I would request Shri Sethiji to uphold all these things though belatedly for the betterment of the backward classes.

PROF. RUP CHANDPAL (Hooghly) : Mr. Chairman, this is the second time that we are discussing the second backward classes commission and we know the reaction of the government, what the government has done.

After Kaka Kalelkar Commission, not less than 14-15 commissions in the different States have been set up which have made important recommendations with regard to how the lot of the backward classes can be improved. The caste problem in our country in the Hindu society is a peculiar feature. For hundreds of years, rather for thousands of years, it is continuing. If you look back into the history you will find that there was no caste system in the primitive period. But, ultimately, with the growth of class society, as Paswanji had put it, with the growth of privileged classes, this caste system grew and was codified later on, which is still continuing today. In the Hindu society in the Indian scene.

We are discussing a very serious report, the Mandal Commission's report. But almost every other day we discuss the lot of the Harijans, the lot of the bacward classes, the atrocities on them, killings, how their women are being raped, these have been regularly, almost every week, reports are being received about the atrocities on Harijans and backward class people.

Paswanji has presented a long history, a long one, to show how deprived they are in the different Government departments, and in the different sectors. But basically, this problem of backward classes is a problem of rural population in a country like ours, because India lives in the villages and the Mandal Commission itself has drawn attention to that, that it is basically the problem of the rural masses we have to be very serious implementing some basic subjects which we have been proposing all the time, but not implementing. One of them is land reforms. It has been said on page 60:-

> 'The net outcome of the above situation is that notwithstanding their numerical preponderance, backward classes continue to remain in mental and material bondage of the higher castes and rich peasantry. Consequently, despite constituting nearly 3/4th of the country's population, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes have been able to acquire a very limited political clout, even though adult franchise was introduced more than three decades back.'

Because the existing means of production are owned by the upper classes. We have nothing to quarrel with the recommendations of the Mandal Commission. They will have

to be considered favourably. Some sort of a concession, protective discrimination, will have to be given, if necessary, to fulfil the needs of the backward classes to bring them into the mainstream. But this is a very small palliative. Only lip service to the problems of these backward people on the election platform will never solve the problem. Something will have to be done and in that regard the Mandal Commission had made very important recommendations but the larger perspective should not be lost sight of; that is, until and unless we do seriously take upland reforms in our country, we implement them, the lot of the backward classes can never improve That has been mentioned by the Mandal Commission itself and while illustrating it has been said that:—

> "The States like Karnataka, Kerala and West Bengal which have gone about the job more earnestly have not only succeeded in materially helping the Backward classes. but also reaped rich political dividends into the bargain."

That should not be lost sight of. Here we are discussing educationally backward classes. Why are they backward till now ? Long ago in the Constitution itself it was written that within a specific time limit universal compulsory elementary education will be implemented.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Within ten years.

PROF. RUP CHAND PAL: Has it been implemented ? Has the Government done that ? Today we would not have to discuss this educational backward classes question had we been serious regarding the land reforms. It would not have been necessary to discuss this question in such a big way as we have to do now. We want that some thing should be done.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Reservation itself was for ten years.

PROF. RUP CHAND PAL : We want it. We support that.

Some sort of protective discrimination, if necessary, will have to be done. But one thing. We shall remember that the situation prevailing in different parts of the country is different. The Government itself—whatever you call it, the action taken report or an apology for it-report—had mentioned that the position obtaining in different parts of the country will have to be taken into consideration. This is so; and the States will have to be consulted but the Central Government is trying to shirk this responsibility, that means that the Government is not at all interested in the welfare of the majority of the people who are downtrodden. Sir, I will not take much of the time of the House These reservations will have to be considered. But I find that those who are already in the job are losing jobs. Look at the jute industry, look at the handloom industry. There, lakhs of people, are being thrown out of employment. This is because of a very, very deepening economic crisis The Government is going to imperialist countries for help, more and more people are moving are below the poverty line. In such a situation by simply demanding reservation in public sector and in Government service even in private sector will never solve the problem; together with demanding some concession for their welfare, we have to remember that the game of the ruling classes, the game of the ruling Party to 'divide and rule' in the name of caste we have seen the poor people, the weaker sections, the down trodden are again and again being divided and sub-divided. We shall have to take care that while demanding some concessions while demanding some reservations for the backward classes, we should not create such a situation which will be utilised by the ruling classes for the purpose of exploiting and to porpetrate the atrocities on exploited classes. Ultimately it will not be a fighting between two castes; ultimately it will be class-battle with all downtrodden classes and as Paswanji has very correctly said, how the privileged classes, he used the word, that word, 'classes' had done and caste is a part of that class. And ultimately by uniting all the downtrodden classes, whatever the classes, ultimately, in the long run we shall have to remove those who are exploiting. We have to save those people who are exploited, to remove those who are in possesion of the means of production.

Sir, as you know, in our part of the country, there is very less of casteism. Inter-caste marriages, even marriages between Hindus and Muslims, take place.

Some developments have taken place because of historical factors. Shri Paswan was referring to Vivekananda. I am referring to a poem of Tagore. He has given the warning long ago that if you do not take care of these people, whom you have left behind, who are oppresed, they will unite themselves; they are aware of those who are owning their land, who have taken away their means of production, who have devided them and exploited them for ages to come.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur) : Mr. Chairman, the subject while we are discussing today has been discussed earlier. I feel that most of the Members will agree with me when I say that there is hardly anything left to be said now. We have expressed our views last time. We have apprised the Government the feeling of the area or the State which we represent. I have heard some of my colleagues when they were speaking on the subject. I have very little to say.

I feel that we must go deep and find out what are the causes which have made us a society divided into Scheduled Castes, Tribes and backward classes. What are the causes ? It is because of some mistake or some defect in our society, which has occurred earlier, may 100 or 50 years back, we are now suffering. If we do not wake up and take some action to uplift society, that section of the society which is socially and educationally backward, we will again be committing the same blunder and we will be retarding the progress further. We must appreciate that.

I do not think anybody in the country is against the proposal that people who are backward must be given all facilities to come up. No Member of Parliament, no political party, no section of society is against it. The intention is very good. That is why the Mandal Commission was set up. I have gone through its terms of reference. It is well-phrased and well thought over. The Mandal Commission has done a good job, after visiting each block and each district in every State and meeting people from all walks of life. So, it is a report which deserves serious consideration by all quarters. The Report was submitted in the middle of 1980. People have appreciated the hard work done by them.

But we are making one mistake. We are trying to give a political colour to it. The opposition parties say that the ruling party is not going to accept. The ruling party says that it is looking into it. We should remember that it is not a political issue. It is in the national interest to implement this Report Let us have that clearly in our mind when we consider the Report.

While accepting the Mandal Commission Report, the Home Minister has to find out some modality of reaching out the persons for whom it is meant. We are fighting for that section of the society, which is socially and educationally backward. I am sorry to say that at present the benefits of reservation are going to a few people or a few sections of that caste. This has to be corrected. Otherwise, in the name of backward castes, some portion of the society will make full use of it.

Also, you must put a time limit till when this reservation will be in force. Otherwise I know that for ever my family will get 10 per cent reservation in employment irrespective of whether I get a second division or only 30 per cent marks in the examination. That should not happen.

And the moment that spirit dies, the national character will be affected and the material coming into our Services will be affected. So, my humble request is that you must give a commitment to the House that this Report will be accepted, as you have a soft corner for the backward classes, so that we can tell our people in our constituencies that the Government is equally keen

Secondly, I would requested you to find out some solution so that the imple-

mentation of this Commission's Report reaches the concerned people for whom we are ghting today and it does not stop in between and people do not misuse it.

I have full faith that Mr. Sethi is helpful to the backward classes and he has a soft corner for them and I hope he will consider the Report and convey our feelings to the G vernment and get it approved as far as possible.

With these words I conclude.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय सभापति जी, मंडल कमीशन के बारे में देश के बाहर और संसद में दोनों ओर से जो विचार व्यक्त किये जा रहे हैं, चाहे वे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वे लोग हों जो पिछड़े वर्ग से हमदर्दी रखते हों, देश में समानता का वातावरण चाहते हैं, उन सबकी इच्छा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र लागू की जाय। हमारे सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्य भी चाहते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाय. लेकिन समझ में नहीं आता कि इसको लागू करने में विलम्ब क्यों हो रहा है? इसको प्रकाशित होने में विलम्ब हुआ, हाउस की टेबिल पर रखने मे विलम्ब हुआ, इसके अलावा इसको लागू करने के लिये चीफ मिनिस्टरों की राय मांगी जा रही है, स्टेट्स से पूछा जा रहा है और अब सचिवों के सामने अध्ययन के लिये रख दिया गया है।

संविधान में जो प्रावधान है, उसके अनुच्छेद 340 के अन्दर बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की स्थापना का प्रश्न है और उसी के अंतर्गत यही कमीशन बनाया गया। सोश्ली और एजूकेशनल जो बैकवर्ड हैं उनको किस तरह से समाज में, शासन में, सत्ता में, आर्थिक स्थिति में, सारे क्षेत्रों में किस तरह से समान स्तर पर लाया जाय, इसके लिये इस कमीशन की व्यवस्था की गई। सोश्ली और एजूकेशनली बैकवर्ड क्लासेज के लिये संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) में व्यवस्था है — जब ये सब व्यवस्थायें हैं तो समझ में नहीं आता कि सरकार इस मामले को अभी तक सुलझाने से क्यों कतरा रही है, जब कि पूरा सदन इस बात से सहमत है, सारे पक्षों की माँग है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जाय।

आज देश के करोड़ों-करोड़ बैकवर्ड क्लासेज के लोगों की निगाह संसद की ओर लगी हुई हैं और मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इस हाउस की प्रोसीडिंग्ज को, आज जो लोग इस बहस में बोल रहे हैं उनके भाषणों को छपवा कर हर गांव सभा में, हर पंचायत में इसकी प्रति भेजी जाय ताकि लोग समझ सकें, लोग जान सकें कि किन-किन को बैकवर्ड क्लासेज से हमदर्दी है और किन-किन को हमदर्दी नहीं है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हू — जो आज बैकवर्ड क्लासेज के आन्दोलन का विरोध कर रहे है. जनता उनको पहचान सकेगी। यह आवाज आज सिर्फ लोक सभा में ही नहीं उठी है, देश के कोने-कोने से यह आवाज उठने वाली है। मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं—खुलकर सामने आइये, छुपी जुबान से विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है, बाहर जाकर घड़ियाली आंसू बहायें कि हमको पिछड़े लोगों से हमदर्दी है और यहां आकर मंडल कमीशन का रिपोर्ट का विरोध करें, पिछड़े लोगो का विरोध करें कोई सत्ता और शक्ति इन 85 प्रतिशत पिछड़े वर्गों का विरोध कर के इस देश में नहीं रह सकती। हजारों सालों से हम लोगों को पददलित और शोषित बनाकर रखा है। मां के पेट से जब कोई जन्म लेता है, कोई पैदा होता है, तो उसके पैर छूने के लिये आगे बढ़ते है, लेकिन दूसरे को जन्म से ही अपमानित होना पड़ता है, अपमान

का घूट पीना पड़ता है। उत्पीड़न और अत्याचार में जिन्होंने जीवन भर अपना जीवन बिताया है और न उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था है और न देश के शासन में उनका कोई अधिकार है और न देश की सेवाओं में और न देश की सम्पत्ति में उनका हिस्सा है और हर तरह से उनकी उपेक्षा है, तो वे ही आज देश में बैकवर्ड है। वे बैकवर्ड क्यों है? जाति के आधार पर इस देश में व्यवस्था की गई और सीधी सी बात है कि इस देश में पहले चार वर्ण थे और उन्हीं में से हजारों की संख्या में जातियां बन गई और उनमें से कुछ बैकवर्ड गिनी जाने लगी। पहले इतनी जातियां नहीं थीं और केवल चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र। वैश्यों के बीच में से सारे के सारे शुद्र आते है चाहे वे अछूत हों या सछूत हों। ये ही लोग बैकवर्ड क्लासेज की सूची में आते है, यही लोग शेड्यूल्ड कास्ट्स की सूची में आते हैं। आपने बहुत सी उप-जातियां बना दी हैं और उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए आपका समाज जिम्मेवार है, जिसने यह जाति और वर्ण व्यवस्था कायम की और इस देश के करोड़ों लोगों को जानवरों के नीचे बैठने के लिए मजबूर किया। एक कुत्ता चारपाई पर बैठ सकता है लेकिन इस देश में एक ऐसे इन्सान को चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं है। मैं कल गृह मंत्री जी से कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि आज किस तरह की स्थिति पैदा हो गई है और कैसा बर्ताव इन लोगों के साथ किया जा रहा है। बदायूं जिला के कटना बचऊ में 200 पुलिस के लोग, पी०ए०सी० के लोग बैकवर्ड लोदी जाति के लोगों को घेरे हुए हैं और उनके घरों को गिरा-गिराकर आग लगाई जा रही है और उनकी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। इस तरह का उत्पीड़न बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के साथ हो रहा है चाहे वह बरेली का भगवानपुर गांव हो, चाहे देवली हो और चाहे कोई और जगह हो। बैकवर्ड और शोषित वर्ग के जो लोग हैं उनकी आज हालत यह है कि उनको मानवता के अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं।

जहां तक काका कालेलकर की रिपोर्ट का सवाल है, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है और अब लोगों के मनों में यह संदेह है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी कहीं रद्दी की टोकरी में न डाल दिया जाए और फिर उसको चुनाव का मुद्दा बनाकर बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को पुनः धोके में डालकर उन्हें फसाया जाए। अब वे इस चाल में फंसने वाले नहीं हैं। कौन नहीं जानता कि इस देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कुम्हार का काम करते हैं, जो लौहार का काम करते हैं जो धोबी का काम करते है, जो मछुवे का काम करते है, और जो मल्लाह और भीवर का काम करते हैं और जो नाई का काम करते है और ये सब बैकवर्ड क्लासेज में आते हैं और आज आपको बैकवर्ड की परिभाषा ढूंढने में दिक्कत हो रही है। आपका मन साफ नहीं है और अगर मन साफ है, तो इस काम को करने में और इसको लागू करने में देरी नहीं होनी चाहिए और तुरन्त इस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। पहले आप हमदर्दी दिखाते थे यह कहकर कि हमारे पास ऐसे लोग एवेलेबिल नहीं है और हमें सर्विसेज के लिए मिल नहीं पाते है। 'नाट एवेलेबिल' आप कहा करते थे लेकिन अब जबकि बैकवर्ड क्लासेज और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग मिलने लगे है, तो आप कहने लगे हैं कि सूटेबिल नहीं है। 'नाट एवेलेबिल' और 'नाट सूटेबिल' कह कर लोगों को नहीं रखा जाता है। सारी योग्यता का ठेका कुछ थोड़े से लोगों ने ही ले लिया है। तो फिर इस देश में भ्रष्टाचार क्यों है और इस देश में अपंग शासन क्यों है। इस

देश में हजारों सालों से इन लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। जो सर्वशक्तिशाली हैं, सम्पन्न है, उन्हीं के पास सत्ता है उन्हीं की सेना है और उनके हाथ में ही शासन है। जब ऐसी बात है, तो फिर यह देश हजारों साल तक गुलाम क्यों रहा। इसलिए आपको इस देश में जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके आर्थिक समाधान के बारे में आप सोचें। कहीं आपने इसमें एकोनामिक क्राइटीरियन रख लिया और बैकवर्डनैस का उसका आधार मान लिया, तो यह भारतीय संविधान के साथ विश्वासघात होगा। एजूकेशनली और सोशली बैकवर्डनैस का क्राइटीरिया मंडल कमीशन से ले कर के कांस्टीट्यूशन तक में दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकार किया है। आर्टीकिल 15 (4), 16 (4) और आर्टीकिल 340 भी सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड के आधार को मानते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन्स को मान करके इस देश के करोड़ों-करोड़ों लोगों का आप समता का मौका दें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जाति के आधार पर जो पिछड़ापन है, वह इसलिए है कि सोशली बैकवर्ड और एजूकेशनली बैकवर्ड क्लासेज न शोषित और दलित जातियों में जन्म लिया है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि वे जल्दी-से जल्दी इस पर अपना निर्णय दें, चाहे इधर दें, और चाहे उधर दें जिससे देश के लोग समझ लें कि पिछड़े हुए समाज के लोगों के आप हमदर्द हैं और उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप इन लोगों के साथ कोई न्याय करना चाहते हैं, तो कोई भी निर्णय आप लें वह जल्दी-से-जल्दी निर्णय लें। अभी यहां 9 अगस्त को वोट क्लब पर 40 संसद सदस्यों ने और दूसरे जन-प्रतिनिधियों ने गिरफ्तारी कराई 11 अगस्त को भारतीय कश्यप निषाद् सभा के तत्वावधान में और मेरे नेतृत्व में हजारों लोगों ने यहां सभा की और गिरफ्तारी कराई। उनकी यही मांग थी कि या तो आप मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कीजिए वरना अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो जाइये।

SHRI D. P. YADAV (Monghyr) : Mr. Chairman, Sir, when I rise to speak on this subject, some of the Hon. Members may apprehend that when I was on that side my stand was something else and, when I am on the ruling party side, my stand will be something different. I reiterate that there has been no change in my views so far as the Mandal Commission's report is concerned.

On that day, on 11th August, 1982, this is what I said when I was on the Opposition benches, in the last paragraph of my speech. I quote :

"I will appeal to the Prime Minister through the House to convene a meeting of the leaders of the Opposition and come down to conclusions regarding the implementation of the Backward Classes Commission's report."

It means, remaining on the other side of the Benches, I felt that this was a matter which needs reconciliation and cool thinking. So, I will appeal to my colleague Shri Satya Deo Singh Ji and Shri Ranjit Singh Ji that since the atmosphere is cool, we should also be considerate and try to solve the problem.

Yesterday only we discussed with the Congress Party General Secretary, Shri Rajiv Gandhi, this very matter with utmost sincerity. About 25 Members of Parliament belonging to the rulling party had a threadbare discussion and I hope Shri Sethi Ji will come forward with some positive and favourable reply. I can only add that the rulling party is not at all averse, rather they are very sympathetic.....

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA (Aurangabad) : Has the Home Minister been instructed, by Mr. Rajiv Gandhi ?

SHRI D.P. YADAV : He is the General Secretary of the Congress Party He has got every right to discuss it in the party. We have expressed our views and almost all the members were unanimous that the Mandal Commission's recommendations should be implemented may be with some modifications as discussed between the Oppositions and the ruling party.

So far Shri Paswan Ji is concerned, I would request only one thing. That he should not go into too much of sentimental speeches. Too much of sentimental speches will aggravate the situation and will not solve the problem. We have to keep in mind the difficulties of both the Governments, the Congress Government and the Janata Government.

A copy of the Kaka Kalelkar Commission's report is with me. It was constituted in 1953 and the report was submitted in 1955. No doubt, the Central Government did not take it into consideration. But it was the Congress regime of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and other Southern- States under the leadership of the Congress Chief Ministership and the Prime Ministership, that they implemented Kaka Kalelkar Commission's report.

4.00 hrs.

जो कुछ भी रिपोर्ट में लिया हुआ आता है, राज्य सरकारों ने उसको लागू किया है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, परंतु केन्द्र में यह बात नहीं हुई। ठीक है यह गलती हुई। इसको हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो काम कांग्रेस राज में हुआ वह भी तो आपके समय में नहीं हुआ, इसको आपको स्वीकार करना होगा। देवराज अर्स ने कर्नाटक में 68% आरक्षण किया जबकि बिहार में कर्पूरी जी मात्र 20 परसेंट और उत्तर प्रदेश में रामनरेश जी 15 परसेंट ही कर दे सके। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस ही बैकवर्ड क्लास रही और जनता पार्टी ने बैकवर्ड क्लासेस का साथ दिया है, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं।

श्री रामविलास पासवान : इस सम्बन्ध में कांग्रेस के प्रस्ताव का अपोजीशन साथ देते हैं लेकिन अपोजीशन के प्रस्ताव का आप लोग विरोध करते हैं।

श्री डी०पी० यादव : इतना ही नहीं आपने जो मेनूफेस्टो निकाला - जनवरी 1977 में— उसमें क्या छपा हुआ है

> "The Janata Party believes that the disparities that separate members of our society from the more educatonailly and economically advanced sections cannot be radically reduced without the policy of special treatment in their favour which will actually provide preferential opportunities for education and self-employment to these sections In this connection, it will reserves between 25 and 33% of all appointments in Government service for the back ward classes as recommended by the Kaka Kalekar Commission."

This is the commitment made by you in your manifesto to the people of India. But instead of implementing this commitment, Prof. Madhu Dandavate, you waived it by appointting the Mandal Commission.

28 मार्च को जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ तो उसमें बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए एक शब्द भी नहीं लिखा गया। जब बहुत हल्ला हुआ तो उसके बाद 20 फरवरी 1978 को दूसरे साल राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक धीमा सा वाक्य आया

> "Backward Classes Commission is being set up to go into the problems of the Backward Classes

and make recommendations to improve their condition."

चलिए, यहां तो कमिटमेंट किया । कमीशन बनाएंगे और बनाया कब, एक जनवरी 1979 को । जब आपको अंदाज लग गया था कि आप शायद नहीं रह सकेंगे । (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह पहली जनता पार्टी की सरकार रही जहां राज्यपाल के अभिभाषण में उन्होंने ऐलान किया कि हमारी प्राथमिकता मण्डल कमीशन को राज्य में लागू करने में रहेगी ।

श्री डी०पी० यादव : राज्यों का तो मैं भी बता रहा हूं कि श्री देवराज अर्स पहले ही कर चुके है । मैं मण्डल कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं । जो प्रेक्टिकल लाचारी कांग्रेस के साथ हो सकता है वही लाचारी आपके साथ भी हो रही हो । लेकिन अब ऐसा अवसर आया है कि 150 संसद सदस्यों ने लिखित में दिया है कि आरक्षण चाहिये । इसमें 71 संसद सदस्य रूलिंग पार्टी के हैं और करीब इतने ही अपोजीशन पार्टी के है । इन्होंने कहा है कि मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना चाहिए । इसलिए मतभेद कहीं नहीं रह जाता है । मतभेद कभी-कभी भाषणों में गर्मी आ जाने से हो जाता है जब पासवान जी चीनी को चींटी खिलाने और गाय को मां कहने की बात करते हैं, तब इधर से हमारे व्यास जी नाराज हो जाते है वास्तविक स्थिति में मैं बताऊं कि हम लोगों को गुस्से में नहीं आना है और माडेलिटी को किसी-न-किसी हालत में तय करना चाहिये ।

एक बात मैं बता दूं कि कभी-कभी यह इंपरेशन इस देश में दिया जाता है कि आजादी की लड़ाई में अमुक जाति के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और अमुक जाति के कारण ही देश स्वतंत्र हुआ । मैं आपको अपने क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं । मेरे यहां एक कांड हुआ था, तारापुर गोली कांड । आजादी की लड़ाई में 1932 में यह हुआ था । जलियां वाला बाग के बाद कहीं अगर हत्या इस प्रकार मशीन गनों से हुई, कहीं पर अगर इस तरह के लोग मारे गए तो हमारे जिले के तारापुर क्षेत्र में मारे गये । मैं कुछ नाम पढ़ देना चाहता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोपोर्शन किन लोगों का है जो मरे हैं, आजादी की बलिवेदी पर चढ़े है :

सवत्री चडी महतो, शीतल चमार, शुक्ल सोनार, संताल पासी, झोटी झा, विश्वनाथ सिंह, सिद्धेश्वर राजहंस, बदरी मडल, वसन्त धानुक, रामेश्वर मंडल, गावीमडल, आशीषमंडल, आदि ।

MR. CHAIRMAN : If you want to mention the caste, mention it. You cannot go on reading names like this.

श्री डी०पी० यादव : इसका मतलब हुआ कि आजादी की लड़ाई मे इन पिछड़े लोगों का भी हिस्सा कम नही रहा ।

दूसरा उदाहरण मैं मिलिटरी रिकार्ड से देना चाहता हूं । यह मैंने मंगाया था । नम्बर 13 कुमायूं रेजीमेंट आफ यादवाज । कुमायूं रेजीमेंट, यादव रेजीमेंट के बारे में जो बात आई है वह मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं :-

Major Shaitan Singh was commanding a company of an infantry battalion deployed at Razangala in the Chushul sector at a height of about 17,000 ft. 114 persons were deployed of one community

and caste and that was Yadava. They all sacrificed their lives. They did not allow Chushul to fall. This is the valour of a backward community; they have sacrificed for the country, they have defended the country, and they should enjoy the fruit of freedom. This is the time for social transformation and social change. I will appeal to this august House to sit down and think about it coolly, and I appeal to the Home Minister, since this is in consonance with the policy of the party which says that 'dynamic movement towards social change is our goal', that the Mandal Commission Report should be implemented; may be with some modifications and changes here and there, but it should be implemented.

MR. CHAIRMAN : Mr Chaturbhuj.

PROF. MADHU DANDAVATE : What about Mr. Mandal ? If on, Mandal Commission Report, Mr. Mandal is not allowed to speak, then who will be.....

MR. CHAIRMAN : There is no discrimination here. But there is no time.....

AN HON. MEMBER : He is the father of the Report.

MR. CHAIRMAN : Let all parties speak. Mr. Chatur Bhuj, you have only six minutes.

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : यह निर्विवाद है, इसमें कोई विरोध की गुंजाइश नहीं है कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिये । 1953 से इसके बारे में आवाज उठती जा रही है । यह आवाज पार्लियामेंट के अन्दर और पार्लियामेंट के बाहर भी बहुत जोर से उठती रही है । संवधानिक संरक्षण उनको प्रदान करने की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनके पक्ष में जाता है, पार्लियामेंट की आवाज भी यही है । फिर भी समझ में नहीं आता है कि 36 वर्ष के बाद भी बैकवर्ड क्लासिस के वास्ते कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है और मंडल कमिशन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है । कितने साल और आपको चाहिये इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए । देश भक्ति के अन्दर पिछड़ी जातियां कम नहीं है, देश प्रेम में किसी से कम नहीं हैं, राज्य की सेवा करने में उन्होंने कम पार्ट प्ले नहीं किया है । नब्बे प्रतिशत भाग इस देश की सेवा करने में, देश भक्ति के अन्दर उनका रहा है । इस मामले में वे अग्रणी है । चाहे खेत की पैदावार हो, चाहे श्रम की बात है, देश की उन्नति की बात हो, कोई भी क्षेत्र हो सब में वे अग्रणी रही है । अलगांव की भावना वही पैदा करता है जिसका देश के लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं है, देश की विभूतियों से कोई सम्बन्ध नही है, देश की उन्नति से कोई सम्बन्ध नही है । ऐसे लोग केवल राजनीतिक करना जानते है और नेतागिरी में ही विश्वास करते है । वे लोग देश की समृद्धि नहीं चाहते है । साफ है कि तब वे बैकवर्ड क्लासिस की समृद्धि भी नही चाहेंगे । हजारों साल का इतिहास साक्षी है कि देश पर शासन उन लोगों ने किया जिनका देश भक्ति से, देश सेवा से कोई सम्बन्ध नहीं था और इस मामले में उन्होंने कोई हिस्सा अदा नहीं किया । लेकिन आप देखे कि संविधान का संरक्षण हमें प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे पक्ष में जाता है जिसने कहा है कि पचास प्रतिशत से अधिक संरक्षण सर्विसिस में नहीं हो सकता है ।

मेरा निवेदन है कि जितने भी मत है चाहे सर्वोच्च न्यायालय का हो, संविधान का हो, पार्लियामेंट का हो, जनता का हो, उनसे आप एक निष्कर्ष पर पहुंचिये । गृह मंत्री को चाहिये कि विरोधी दलों और ट्रेजरी बैंचेज के सदस्यों के साथ बैठकर देश की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल, जो मांग हो रही है, उसके अनुसार कुछ निर्णय करें । आज छोटी-छोटी जातियों को छोड़िये जो अलगाव पैदा करने की कोशिश कर

रही हैं, यदि आपने लम्बा समय खींच दिया तो स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिये यह भावना पैदा न होने दें।

आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक सांस्कृतिक, शिक्षण क्षेत्र हो और जितने उद्योग धंधे हैं, किसी भी क्षेत्र के हों, उनमें आज बैकवर्ड क्लासिस की स्थिति यह है कि 1 परसेंट या 2 परसेंट से ज्यादा व्यक्ति कहीं भी नहीं हैं ? ऐसा क्यों है देश के इस वर्ग को क्यों वंचित किया गया ? इन्हें राजनीति से किस ने वंचित किया ? आप सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखें हमारे देश के 34 परसेंट में से कुछ बड़े-बड़े इलाकों में शिक्षा का परसेंट 26 परसेंट है लेकिन बैकवर्ड क्लासिस का प्रतिशत 6 से ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों है ? यह भेदभाव कौन कर रहा है ? ये राजनीतिज्ञ हैं जो अपनी मन स्थिति से देश को ऊपर नहीं उठाना चाहते, समृद्धि की ओर नहीं ले जाना चाहते।

मैं एक ही मांग करूंगा कि अगर संवैधानिक कर्तव्य आपने नहीं निभाया, संविधान के निर्देशक तत्वों की पालना किसने नहीं की ? 36 वर्ष के अपने शासन में आपने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। फंडामेंटल राइट, जो निर्देशक तत्व संविधान में दिये गये हैं, उनकी पालना हेतु आपको आगे बढ़कर इनका संरक्षण करना चाहिये था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आज आपको किसी भी जगह कहने का अधिकार नहीं है कि इस देश की प्रगति के लिये आपने कोई कार्य किया है। हर क्षेत्र में जब तक पिछड़ा वर्ग आगे नहीं आयेगा, कृषि को देख लीजिये, आंकड़े उठाकर देख लीजिये किसान का बेटा इनमें नहीं जा सकता है लेकिन बड़े-बड़े राजनेताओं के संरक्षण में पलने वाले चमचा-गिरों के लड़के इसमें आ जाते हैं। किसान का बेटा जो देहात में है और शत-प्रतिशत देहात का बालक है वह इसमें नहीं जाता।

एक खतरा और पैदा हो रहा है, इस देश में अमीर-गरीब की खाई पैदा हो रही है। जाति और धर्म टूट रहे हैं लेकिन अमीर-गरीब का भाव इस देश को कहां ले जायेगा, यह संघर्ष हमें कहां ले जायेगा, खून-खराबा कहां ले जायेगा ? यह ट्रेजरी बैंचेज और पार्लियामेंट के सोचने का दायित्व है, आने वाला समय ज्यादा इन्तजार नहीं करेगा। यह खाई बढ़ती गई तो ठीक नहीं होगा। शिक्षण संस्थाओं में गरीबों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। गांव में 500 और 300 लड़कों के पीछे एक अध्यापक है। शहर में प्राइवेट स्कूलों में अच्छे-अच्छे लड़के हैं, प्राइम मिनिस्टर का लड़का और दूसरे जो सेंट्रल स्कूलों, में माडर्न स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वह आगे जायेंगे या आप आशा करते हैं कि देश का 76 प्रतिशत व्यक्ति जो देहात में रहता है, क्या वह आगे आ सकता है, क्या आई०ए०एस० और आई०पी०एस० में जा सकता है ? हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

आज हम कहते हैं कि इस देश में 4,000 जातियां है, इनमें 3,000 जातियों का एक भी लड़का पटवारी से लेकर कहीं किसी ओहदे पर नहीं है। मैं मांग करता हूं कि गंभीरता से इस पर चिन्तन करके राष्ट्रीय हित में, अमीर-गरीब की खाई को पैदा न होने दें, देश-हित और राष्ट्रीय हित पैदा हो, सेवा का भाव पैदा कर के ऐसी कल्पना को साकार करें जिससे जाति और वर्ग को बढ़ावा न मिले।

मेरी मांग है कि सभी दलों को बैठकर, गृहमंत्री जी इस पर विचार करें, चिन्तन करें। ऐसा तो नहीं है कि देशभक्ति और देश-सेवा टूट रही हो, इने-गिने आदमी इस देश की राज सत्ता पर जाकर देश को खून-खराबे की ओर ले जा रहे हों। इससे बचाने के लिये आपको

चिन्तन करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि राष्ट्र भक्ति से औत-प्रोत लोगों की कान्फरेंस बुलाकर इस पर विचार करके मंडल आयोग की रिपोर्ट को आप लागू करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज): सभापति महोदय, मंडल आयोग की रिपोर्ट और अनुशंसाओं पर पिछले सेशन में भी विस्तार से चर्चा हुई थी और आज फिर उन पर चर्चा हो रही है।

आज परिस्थिति यह है कि पिछड़े वर्ग के लोग विभिन्न सरकारी सेवाओं में उस अनुपात में नही हैं अथवा विभिन्न सरकारी योजनाओं से उस अनुपात में लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिस अनुपात में होना चाहिये। पूरे देश में उनकी आबादी 52 प्रतिशत है। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सदियों से पिछड़े वर्ग और शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग पद-दलित रहे हैं। निश्चित रूप से इसके पीछे हिन्दू धर्म की व्यवस्था रही है। वेदों, उपनिषदों और मनुस्मृति को देखने से पता चलता है कि उस समय की व्यवस्था के अनुसार कोई शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता था। चालाक और होशियार लोगों ने अपने लाभ के लिए यह नियम बना रखा था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के किसी व्यक्ति के पास सम्पत्ति हो जाए, तो राजा को अधिकार है कि वह उसे छीन ले और उस व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल दे। यह हमारे समाज की रचना की पृष्ठभूमि है।

देश के आजाद होने पर संविधान में आर्टिकल 340 का समावेश किया गया। इस सम्बन्ध में स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भावनाएं थीं, अभी श्री पासवान ने उनको पढ़कर सुनाया है। जिस तरह आज कहा जाता है कि देश में रिजनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, उसी तरह समाज में कोई ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिए, जो दूसरों की तुलना में कमजोर या पिछड़ा हो। आज कहा जाता है कि काम्पीटीशन में सब के लिए समान अवसर है। जब समाज के सभी लोगों के लिए समान पृष्ठभूमि, परिवेश और वातावरण नहीं है, तो समान अवसर की बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जब समाज के सभी लोग पब्लिक स्कूलों में जा सकेंगे और सबको समान पृष्ठभूमि प्राप्त हो सकेगी, तब किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी।

यह ठीक है कि हम रिजर्वेशन को बहुत दिनों तक नहीं चला सकते। मैं गृहमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमें यह ध्यान देना है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए जो रिजर्वेशन किया गया है, उसको पूरा किया जाए और दूसरी तरफ जो लोग इन वर्गों में शामिल होने से छूट गए हैं, उनको भी शामिल किया जाए। गृहमंत्री पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सी ऐसी जातियां हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स ओर शिड्यूल्ड ट्राइब्ज में होनी चाहिए थीं, लेकिन वे नहीं हो सकी हैं। हो सकता है कि दो-चार जातियां गलत ढंग से उनमें समाविष्ट हो गई हो। अगर सरकार समझती है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें है, जो मानने योग्य नहीं है, तो वह उनको न माने, लेकिन इस बुनियादी बात के बारे में दो राय नहीं है कि सारे समाज को एक स्तर पर लाना है। समय का तकाजा है कि हम सब लोग इस बारे में विचार करके इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करें।

विरोधी पक्ष से मैं कहना चाहता हूं कि वे लोग मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को राज-

नैतिक दृष्टि से भुनाने का प्रयास न करें। विरोधी पक्ष को यह नहीं कहना चाहिए कि इधर के लोग एन्टी-बैकवर्ड क्लासिज या एन्टी-शिड्यूल्ड कास्ट्स है। इस मामले को वोट की राजनीति से कोसों दूर रखना चाहिए। हम देखते हैं कि उधर के बैठने वाले जातीयता और साम्प्रदायिकता का नापाक संगठन कर रहे हैं — चौधरी चरणसिह और जनसंघ वाले एक दूसरे के साथ मिल रहे है। हम लोग कांग्रेस की बुनियादी नीतियों — सैक्युलरिज्म, सोशलिज्म और लोकतंत्र — पर चल रहे हैं। आज समय की आवश्यकता है, हमारी कांग्रेस की जो बुनियादी नीतियां हैं, समाजवाद की नीति है, सैक्यूलरिज्य की नीति है, लोकतन्त्र की नीति है और गुट-निरपेक्षता की नीति हैं — इन चार शब्दों को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि सर्विस में हमारी संख्या कम हैं। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में भी इसी प्रकार की हालत है। आजकल सर्विस एक प्रैस्टिज का सवाल है, पावर की बात आ जाती है। जिस समाज का कोई आदमी कलैक्टर बन जाता हैं, निश्चित है कि नीचे वालों का मोरेल ऊपर उठ जाता है। यह बात स्वाभाविक है। आदर्श की बात नहीं है। यह बात सही है कि आप रिजर्वेशन करने जा रहे हैं। जो लड़का, जो छात्र उस कम्पीटीशन में आ जाता है, उस को न रखिए, नीचे के लोग जो उस प्रतिशत में नहीं आ रहे हैं, उनको मौका देने की जरूरत है। तब तक उनको मौका देने की जरूरत है, जब तक समाज समान स्तर पर न आ जाए। मैं पासवान जी की बात से मुताफिक नहीं हूं, जैसा कि उन्होंने कहा है कम्पीटीशन में वही आता है, जिसके पास बुद्धि है। मैं कहता हूं कि बुद्धि किसी की वपौती नहीं है। मैं आज पढ़ लिख लिया हूं और आज संसद सदस्य हूं। लेकिन आज जो देहातों में हमारे भाई हैं और शहर में जो भाई बन्धु हैं यह कहे कि आपने समान अवसर दिया है, किसी कम्पीटीशन में बैठायें, तो यह न्यायोचित बात नहीं है। देश की परिस्थितियों को समझकर, देश की भावनाओं को समझकर, राष्ट्र के उच्चतर हितों को ध्यान में रखते हुए, मंडल आयोग की उन अनुशंसाओं से, जिनसे देश का भला होता हो, समाज का भला होता हो, राष्ट्र की एकता मजबूत होती हो, उन पर विचार करना चाहिए। लेकिन मैं पासवान जी, यादव जी और विरोधी दल के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाये और यह न कहें कि हम लोग नहीं रहते तो यह कांग्रेस सरकार नहीं मानती। हमारी प्रधान मंत्री जी स्वयं बहुत चिन्तित हैं। राज्यों को इस बारे में लिखा है और उनकी भी अनुशंसा आएगी। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हू कि सरकार जब कोई निर्णय अपने आप लेती है, तो आप कहते हैं कि राज्यों की उपेक्षा की जा रही है और जब राज्यों से राय मांगी जा रही है, तो आप कहते हैं कि सरकार इस रिपोर्ट को मानती क्यों नहीं है। हमारी केन्द्रीय सरकार ने और हमारे होम मिनिस्टर ने विभिन्न राज्यों से प्रतिक्रिया मांगी है। हमारी सरकार को मौका मिलना चाहिए कि वह हर चीज पर विचार करें। यह बहुत ही नाजुक मसला है, हमें उन लोगों की भावनाओं को भी देखना पड़ेगा। जब गुजरात में शैड्यूल्ड कास्ट के बारे में आन्दोलन चल रहा था तो हमारे अटल जी "अगर" और "मगर" करके बात किया करते थे। इसको कैसे ठीक करें। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है, इसलिए हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। यदि इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाएगी तो देश के साथ बड़ा धोखा होगा। इसलिए मंडल आयोग की जितनी अनुशंसाओं को लागू करना संभव हो, उतनी धाराओं को लागू करें, जिससे समाज में असंतोष पैदा न हो सके। जो असंतोष बढ रहा है, उसको रोकने का प्रयास करें।

मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे माननीय गृह-मंत्री जी विभिन्न राज्यों से राय लेकर इसको स्वीकार करेंगे । इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । (इति)

SHRI T. NAGARATNAM (Sriperumbudur) : Mr. Chairman, Sir, I am very glad that I have been given this opportunity to take part in the debate on the non-implementation of the Mandal Commission Report and I urge the Government to implement the recommendations of the Report soon.

Having exercised by Article 340 of the Indian Constitution, the President appointed a Backward Classes Commission to investigate the conditions of society and educationally backward classes of our country under the Chairmanship of Shri B.P. Mandal. A notification to this effect was issued on 20th December, 1978. The Commission has also completed after thorough investigation and studied all spheres of our country. The Report has been submitted to the Government on 12th December 1980 for which I must congratulate the Janata Party. Before it came to power it assured the backward communities with its 1977 Election Manifesto that "it will reserve between 25% and 33% of all appointments to Government services for the backward classes, as recommended by the Kalelkar Commission. The Janata Party, after assuming power, did not keep up its promise in abeyance, but it tried to implement the reservation after getting the Report of the Mandal Commission

Unfortunately, but fortunate to the Congress Government, the Janata Party has been broken into pieces and Parliament was dissolved in the year 1979. Therefore, the Janata Government had no opportunity .o implement the Mandal Commission Report. But the Congress (I) Government received the Mandal Commisssion's Report on 12th December, 1980. I ask the Minister through you, Sir, why is he hesitating to implement this Report ? During the debate on Mandal Commission Report the ruling side as well as the opposite side Members supported and suggested to the Government to implement the Report. But the Congress Government has been keeping this Report in Pickles jar. I urge the Minister through you, Sir, that the Report should be implemented.

Sir, throughout India the fourth Caste—Sudra a had been denied education, social status and opportunity to taste anything good in life for more than 20 centuries, because of Hinduism which has been divided as Savarnas and Avarnas.

The Avarnas are untouchables and the Savarnas have again been divided into four—Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras.

In the year 1873, the pioneer was Jothi Rao Phule of Maharashtra, who started a non-Brahmin movement in India.

Later the Maharaja of Mysore, who happened to be a Sudra, appointed a Committee under Sir, Leslie Miller, the then Chief Justice of Mysore in 1918 and this Commission recommended reservation of 75% of the jobs for non-Brahmins including the Muslims and others.

In 1916, the non-Brahmin leaders with the object of liberating the Sudras and untouchables from upper castes, formed a party, i.e. Shri P. Thiagaraya Chettiar and Dr. T.M. Nair started the South Indian Liberal Federation (Justice Party). They came to power in Madras Presidency at the end of 1920, issued an order on 16.9.1921 (Public Ordinary Service) G.O. No. 613 reserving jobs to all communities.

Later, two G.Os were passed—dated 15.2.1922 and 6.2.1924 but due to severe criticism and opposition raised by the religious, social and political upper-classes, till 1927 those G.Os were not implemented, in Tamil Nadu i.e. Madras Presidency.

The first G.O. came on 4.11.1927 which implemented reservation in jobs to all communities—Brahmins, non-Brahmin Hindus, Muslims, Anglo Indians, Christians and the Scheduled Castes in Madras Presidency. Later, several orders were passed for uplife of backward and scheduled Caste People.

The father of our Constitution, Dr. Ambedkar played a significant role in demanding and achieving reservation to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all walks of life.

But after 36 years of our achieving independence, even the reservation of 15% for SCs and 7-1/2% for STs is not properly fulfilled. They have been deprived by bureaucratic and upper caste officers. They have boldly disobeyed the Government and constitutional policy. Therefore, I urge the Government that this should be looked into. The disobeying officers may severely be punished.

Periyar E.V. Ramaswamy had been demanding separate reservations to the backward classes ever since 1919 Later, in 1947, the Congress Government granted separate reservation to backward classes at the State level in Tamil Nadu. Thereafter, Periyar Ramaswamy agitated, and the Tamil Nadu Government issued a G.O. revising communal reservation as follows :

> S.C. and S.T.—16%; backward classes, including Muslims 25%; Open quota 59%.

MR. CHAIRMAN : Kindly wind up.

SHRI T. NAGARATNAM : I am very proud to say that my leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, the then Chief Minister of Tamil Nadu raised the percentage—backward classes 31%; SC and ST 18%, in 1971. During 1980, the AIADMK Government in Tamil Nadu increased the percentage of reservation to backward classes to 50%, but it has not raised it for SCs and STs.

The other three States in the South have also done like this : the Karnataka Government has raised it to 35% for backward classes, and the Andhra Pradesh Government to 25%, and the Kerala Government to 40% i.e. for allocation of jobs and admission to educational institutions.

There is no justification why almost all jobs in the Central Services should be held by the upper classes, in the name of merit and efficiency. For example, in IAS, there were 3546 posts, as on 1.1.979, out of which more than 2,000 were held by upper clases, who form 5% of the population. In Tamil Nadu, out of 257 IAS officers as on 1.1.1980, 122 were Brahmins; 59 were upper castes, 34 SCs and STs, and 42 backward classes, including Muslims and Christians.

Take the Income-Tax Department. In the Tamil Nadu region, as on 1.1.1979, there were 319 gazetted officers, out of whom 171 were upper castes.

Take the judiciary. The position of B.C. and S.C. and S.T. is totally neglected and ignored in the higher and the highest-judiciary forum.

It was stated by the Hon. Minister of Lawon the floor of this House during October 1981 that out of 328 judges of the High Courts in India, 20 belonged to B.C. and only 4 to S.C. and none to S.T. The others are occupying the judiciary. I urge the government to implement the Mandal Commission Report.

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : सभापति जी, इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर यहां पर चर्चा हो रही है। यह आज ही नहीं हो रही है, यह बहुत देर से हो रही है और तब से हो रही है जबसे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस हाउस में पेश हुई है। इस रिपोर्ट पर बहस के समय जातिवाद को ले कर रिजर्वेशन मांगी जाती है। हमें सोचना पडेगा

कि हमें जातिवाद को खत्म करना है या जातिवाद को आगे बढ़ाना है ।

इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में उड़ीसा की 224 जातियों को बैकवर्ड क्लासिज माना गया है । इन 224 जातियों में बहुत सी ऊंची जातियां भी हैं । अगर सरकार इन जातियों को बैकवर्ड क्लास मान लेती है तो हमें यह सोचना होगा कि क्या हम सबको सुविधाएं दे पायेंगे या नहीं । हम आज देखते हैं कि आज हम जिन जातियों को सुविधाएं दे रहे हैं उनमें कुछ ही आगे बढ़े लोग ही आगे बढ़ रहे हैं । आपको सुनकर हैरानी होगी कि शैड्युल्ड कास्टस और शैड्युल्ड ट्राइब्स में जो लोग आगे बढ़ चुके हैं वे ही और आगे बढ़ रहे हैं और अधिक आगे बढ़ते जाते हैं । इन जातियों में बहुत अधिक लोग ऐसे हैं जिनको यह तक नहीं मालूम है कि हम कैसे आगे बढ़ें । बिहार में एक जाति मुसहर है और उड़ीसा में एक जाति मनकड़िया है । ये दोनों जातियां प्रिमिटिव हैं और इन जातियों को सहुलियतें देना तो अलग रहा, इनको आइडेन्टिफाई करना मुश्किल है क्योंकि ये जातियां घूमती रहती हैं ।

हमारा लक्ष्य है कि हमें सबको सहुलियतें देना है, सबको मदद देना है और सबको आगे ले जाना है । आज हमारे सामने यही समस्या है कि हमें जो पीछे पड़े हुए हैं उनको उठाना है और हम उनको कैसे जल्दी से उठायें । जातिवाद से तो हम आगे नहीं ले जा सकते हैं । जातिवाद को तो हमें रोकना होगा । अगर हम जातिवाद की दिशा में जायेंगे तो यह झगड़ा बहुत बढ़ जायेगा और इससे देश की एकता और अखंडता पर असर पड़ेगा । इसलिए हमें इन सब पहलुओं पर सोचना होगा ।

मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उनमें काफी गल्तियां हैं । उनको हमें ठीक करना पड़ेगा । अगर हम इन गल्तियों को नहीं देखेंगे और ठीक नहीं करेंगे तो इनसे हमारा नुकसान होगा । हम बजाय आगे जाने के पीछे जाने लगेंगे । आज बीसवीं सेंचरी (20th Century) है और हमको आगे जाना है । हम जातिवाद को ले कर आगे नहीं जा सकते । जातिवाद के आधार पर कोई बंटवारा हो, इसे मैं पसन्द नहीं करता हूं । एक सेन्टीमेंट (Sentiment) की बात है, एक कंट्रोवर्सी (Controversy) की बात है । मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता ।

15 अगस्त को प्रधानमन्त्री जी ने जो घोषणा की है उसको देखते हुए अब मण्डल कमीशन का उतना महत्व नहीं रह गया है । प्रधानमन्त्री ने कहा है-

Two employment schemes have been announced by the Prime Minister. That will assure a job for every landless rural family and self-employment to educated jobless in the cities and towns. This scheme will cover 2.5 lakh educated youngmen and women and three lakh families in the villages every year.

इससे प्रधानमन्त्री देश को एक नई दिशा में ले जाना चाहती है । देश की अर्थ नीति और सामाजिक नीति को उन्होंने अच्छी तरह से समझा है और बताया है कि यह होना चाहिए । आज इस बारे में कुछ करने की आवश्यकता है । इसके लिए संविधान में परिवर्तन करना होगा ।

हमने अपनी कमेटी के सामने कहा है--

All those families living in India below the poverty line should be identified and issue them a family card or family identity card and give them the full benefit for their educational benefit, employment opportunity and economical benefits under different schemes.

हमारा यह कहना था कि जितने भी परिवार हिन्दुस्तान में पावर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं उन सबका आईडिएंटीफिकेशन होना चाहिए और उनको सारी सुविधाएं दी जानी चाहिएं। उनको आर्थिक सहायता, एम्प्लायमेंट, एजूकेशन की सुविधा दी जाए। उनको कम-से-कम ग्रेजुएट होने तक मदद दी जाए ताकि पिछड़े लोग आगे आ सकें। इससे देश को लाभ होगा। इससे देश की अखण्डता और एकता को लाभ होगा। माननीय प्रधानमन्त्री का प्रोग्राम अच्छा है। इस बारे में हमें सोचना है। मण्डल कमीशन में जो कट्रोवर्शल है उनको लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए और जात-पात में नहीं जाना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BHOGINDRA JHA (Madhubani) : Mr. Chairman, Sir, this issue of backward class reservation in the context of the social divison in our society began just after Independence. Social division based on caste began when the class division in our society itself began. Prior to that, in our society there was no division between the rich and the poor. There was no caste based on birth. I am saying this because many of my friends speak about this without knowing the reality. There is no mention of caste based on birth in any Vedas or Upnishads or any ancient original philosophical text. The same family gave birth to Brahmin, Kshatriya, Vaisya and Shudra based on profession. But when the classes arose, one became rich by exploiting others, then two things had happened in our society. The producer of wealth was declared untouchable. Thereby the produce of his labour cannot be utilised by him or her. The producer of wealth was declared as Shudra, the untouchable and the re-producer of human species, the mother, was also put in the same category. So, two enslavement took place. The latest philosophy of the Manusm riti which was composed in about a thousand years, also signifies the feudal set up. That is why the tragedy began because when an untouchable produces the wealth, it does not get polluted. He can plough the land. He can plant paddy, wheat or whatever it is. He can harvest it. thresh it and store it, but the foodgrains do not get polluted. But at the time of eating, it gets polluted from the producer himself. This is not DHARMA. But this is a naked class exploitation and oppression couched in social terminology. Thereby this caste based on birth in place of the former varna based on profession, get established in India. The Islam came. But it was also infected and got divided into Sheikh, Syed, Momins, Rayeens, etc. This caste based on birth gave immobility to our social order based on landed property. I have fought the whole of my iife against it and given my blood several times. Unless you eliminate the land ownership, particularly by the absentee and rich owners, this caste problem is not going to be eliminated.

Nowadays, our caste and communal problems have also become modernised. One comes from England after taking beef But here many of them began Muslim baiting on that very ground. So, a new type of custom came in. Many people do not have sacred thread but in the name of that thread, they committed atrocities aad violence against the social backward castes and others. It was in this context that our Constitution makers saw to it that the most oppressed in our society, the SC & ST, the real producers of wealth, be elevated and reservation was made for the SC & ST in the Constitution itself. But upto this day, that has not yet been fully implemented at any level. With regard to the SC & ST in the fourth grade, to some extent, serious efforts have been made in that direction. But in the upper categories the picture is very unsatisfactory. About other backward classes the matter was mentioned in the Constitution but to be decided later. Again, many of my friends had forgotten the class character. We eliminated the statutory landlordism but a new class of rural rich, the kulaks, emerged. They became the owners of wealth and oppressors of the actual toilers in the field. They belong to the former so called upper caste as well as to the socalled backward caste also. Many massacres and atrocities in the recent years against the Scheduled Caste people were committed by both categories of rural rich.

The massacres and atrocities committed in Belchi and Pathada committed by the rural rich belonging to the so called backward castes. This is the problem of the neo-rich. I do not know of a single usurer in the whole country who charges interest from the other caste people but not from his own caste men. If any friend helps me by giving a single example, I will be enlightened. I do not know a single officer who takes bribe from other caste people but not from the people belonging to his own caste. On these issues, the castes do not come in the way. Simply the caste problem is utilished to disrupt our democratic movement. Even among the Scheduled Castes there are sub-divisions. One caste gets polluted by taking the food of other caste. For example, a Mochi and a Paswan do not take the food of each other. There are numerous sub-divisions among the broad caste categories. But that is the reality which has to be eliminated in the interest of our developing democratic set up. In such a situation, I insist that some basis has to be evolved which can unify the democratic movement and the broad masses and at the same time, remove the age old barriers of oppression—social and economic oppression. That is why I said that in Bihar during the Janata Party rule, the problem was raised. The Janata Party got itself divided and devided the whole society.

But, in the end, we played the part and this problem was solved.

The recommendation of the Mandal Commission for 20 per cent reservation for other backward castes must be accepted. It should be applicable to those whose income below the income tax level. Otherwise, the really backward people will never get any opportunity; the exploiters among the backward castes will usurp the position of the really backward.

Similarly, I want that the women should get a fair share. They are 50 per cent of our population. But in every caste they are oppressed, even among harijans, I care say. So, I demand that in every caste group there should be 25 per cent reservation for women. It is only when women are not found that you can take men from that very caste against those reserved posts. We cannot usher in a classless society so long as the women are not free. That is why I say tha t every reccommendation of the Mandal Commission has to be deeply studied and implemented.

In Bihar reservation was made for those below the income-tax limit. There was 3 per cent for women, 3 per cent for the poorest among the so-called forward castes, 12 per cent for the more backward among the backward castes and 8 per cent for the less backward among the backward castes. I am very much surprised, rather I am sorry, that my friends of the ruling party in Bihar at that time are not mentioning this achievement. I do not understand it. It looks like an unmarried mother, who is ashamed of owning her own child.

Now there are both social and economic criteria. So, let us clearly say where we want to go. Do we want the poor backward people to remain where they are ? If we do not want that position to continue. then the reservation should be only for those who are below the income-tax limit. There should be reservation for women also. In the Central Government services the preference for Scheduled Castes and Tribes is not fully implemented; nor is it being done in any of the States. Similarly, reservation must be made for the other backward castes. 25 per cent reservation for women should also be ensured among all the classes.

Again, I appeal to this House, let us not further divide the Indian nation or retard the democratic movement. We must undo the injustice; we must now allow further injustice to be perpetrated. For that we have to provide jobs for all irrespective of caste, self-employment for all irrespective of caste. That must be adopted as a policy and this House must strive for that. Then only we can solve this problem,

SHRI B.R. BHAGAT (Sitamarhi) : Mr. Chairman, this is the third time that the Mandal Commission Report is being discussed in this House. I am very happy to note that on all those occasions, and also in the present case, the House displayed near unanimity on the recommendations and contents

of the Mandal Commission Report. Even the discussion today shows that Hon. Members from both sides of the House are pressing the Government to implement the Report as early as possible.

The Government also, I must say, in response to the demand, desire and persuation of the House, are moving in that direction. After the first discussion the Home Minister announced that the matter was being considered and that it will be referred to the Committee of Chief Ministers.

The matter was discussed in the whole Committee of Chief Ministers and when, for the second time, the Commission's Report was discussed, the Home Minister announced that the Chief Ministers have discussed it and the matter has been referred to the Committee of Secretaries for examining the modalities in detail. It means, I presume that the Chief Ministers Committee considered it and they accepted this recommenda tion of the Mandal Commission with some differences. For example, from what I read in the papers I find that it is said that some Chief Ministers expressed that the criteria should be economic and in some States there have been some inconsistencies in the preparation of lists. But the fact is that the Home Minister announced, after the discussion in the House, that 'the matter is being examined in detail by a Committee of Secretaries.' So, it is absolutely clear that the Government is actively engaged in this and today when we are discussing this, I think the hour has reached when the Mome Minister may be able to say something positively and sympathetically that they will be able to take decision on this matter very soon.

I would only urge that we should maintain the spirit of concensus on this.The Members from both sides have taken active interest towards the implementation of this Report. While people in the Opposition have agitated, those in the Congress (I), the Ruling Party Members, have also met in a conclave, they have discussed among themselves; only this morning we discussed with the Home Minister and other Ministers of the Cabinet and when the Memorandum was submitted to the Prime Minister, as was said by Mr. D.P. Yadav, it was by 150 Members, almost half and half from both the sides. So, I would only urge that let us maintain the concensus on this issue because if we introduce any party element or any partisan element, some of us may gain and some of us may lose, but the ultimate loser will be the backward classes whose cause is dear to all of us.

Even at this stage, although this has been discussed, I would like to make two or three things clear by touching the heart of the problem. Often times it is asked : What should be the criteria for the implementation? So far as the question of criteria—the question of economic criteria or the criteria of the caste--is concerned, I said this question is settled. It is only at the Centre the recommendation is not implemented. But most of the States have set up Backward Classes Commissions and have accepted and adopted and implemented the recommendations of the State Backward Classes Commissions and with all the Backward Classes Commissions, the recommendation was that either the reservation or the stipends or the other benefits should go on the basis of castes. And a number of lists have been drawn up. It is being done everywhere. Whether it is the Congress State Governments or the non-Congress State Governments, there is unanimity about this. Therefore, I do not understand why this question should arise so far as the implementation of the Mandal Commission Report is concerned about the reservation in the Union Services and other facilities.

This is one aspect. The second aspect is that this question has been settled in the Constitution itself and the large body of case laws that has been there. These two aspects are important. They have settled this question once for all. For example, what does our Constitution say about it, which is the distinctive feature of the Indian Constitution, distinctive from any Constitution in the world ? When we talk of socialism, when we talk of revolution, we do not talk of only classless revolution or casteless society. We talk of, in our Directive Principles, casteless and classless society.

15.00 hrs.

Why ? Because India is the only country which has been caste-ridden and where we have heard from Shri Ram Vilasji or some other Members how caste has played a horrifying role in the history in exploiting brother and brother and man and man. It is the most blackest spot in the otherwise most luminescent Indian civilisation where we talk of advoitwad, where we talk of man is equal to God himself, where we talk of वसुधैव कुटुम्बकम्. On the one hand the Indian civilisation and the Indian culture talks of the whole world of brotherhood, on the other hand we have cast perpetration of the worst kind. This is the reason why our Constitution says, no, we will not only have classless society but have casteless society. This is one aspect of it.

Our great leader Pandit Nehru talked of Article 15 (4) and 16 (4) in the Select Committee.

15 (4) : "Nothing in this article.....shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens....."

16 (4) : " Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens....."

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh) : Panditji initiated it.

SHRI B.R. BHAGAT : On the concept of socially and educationally backward, Panditji in the Select Committee explained this departure i.e. 'any backward class of citizens' and 15(4) 'advancement of any socially and educationally backward classes of citizens'. He explained this shift, this difference in the Committee. Article 15(4) was brought in line with Article 340. It provides that the Backward Classes Commission may be set up for socially and educationally backward class of citizens. Article 340 is an instrument for determining who are the backward classes. On the very concept of backward classes Pandit Nehru says this—educationally and socially backward classes.

The Constitution no where talks of ecomic criteria or economic backwardness. Pandit Nehru is the initiator of this. And, therefore, as Congressman, or as those who had fought for the freedom of the country and have left us as Indians, we must keep in line with what is given in the Constitution. It gives very clear definition who are backward classes. Dr. Ambedkar the law giver, the modern Manu, the framer of the Constitution, he defined it in absolutely clear terms. Dr. Ambedkar, the then Law Minister was more forthcoming when he observed what are called backward classes—"Nothing else but a collection of certain castes". These are the backward classes. Backward classes are nothing more but a collection of certain castes. Whether it was Kaka Kalelkar Commission or whether it was a number of State Commissions, they all came to one recommendation that when we are to determine the backward classes in Article 340 it has to be only educationally and socially backward. They went into all this collecting figures and moving round the country and the Indian States. On that basis they determined certain communities. They said that these are backward classes.

At this moment I would only plead that we should not go into this. This matter is settled for all purposes, Constitutionally, legally, morally for all of us. This is the heritage coming down from the founders of this country. There were men like Pandit Nehru and Dr. Ambedkar who gave us the Constitution.

There is a problem which we have to deal with. I have all the sympathies with the Government when they are dealing with it. It is a very complicated problem particularly in the northern States. In the southern States, this problem is solved and

accepted by the society. Even the members of the so-called upper caste have accepted it. When Mr. Devraj Urs, the Congress Chief Minister after Hanaver Report made reservation of 66 per cent, the matter went to the court and the court upheld it. It is a very important judgment.

There are two aspects. Article 16 (4) is for the reservation of backward classes. Article 16 (3) reads :

> "Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing, in regard to a class or classes of employment....."

On the basis of Hanaver recommendation, Mr. Devraj Urs made reservation for other classes of citizens, other than backward classes. Of course, the courts decided that under these categories of SC&ST and backward classes the reservation should not be more than 50 per cent; otherwise, it will be discrimanatory and *ultra vires*. On that basis, the Mandal Commission's report has made a recommendation for 27 per cent because 22 per cent is for SC & ST, making it 49 per cent. But the Mandal Commission's report says that for other communities, the poorer sections, the economically backward among the upper classes suitable reservation should be made, but since this is not within the purview of its terms of reference, they are not making a reference to it.

I would, therefore, suggest one thing. It may be a way out for the Government also. I know, they face a serious problem because there is a large unemployment among the uppper classes youngmen in U.P., Bihar, Rajasthan and in other northern States. When reservation is being made for backward classes they think that their jobs are being taken away. I suggest that economic criteria and caste criteria under these articles 16 (3) and 16 (4) should not be mixed up and they should be separated. There should be a caste criterion which has been accepted Constitutionally and legally and should be applied in the case of Mandal Commission's report with regard to the Centre and we should make reservation for economically poorer sections of the upper caste people separately so that there is a balance and there should be acceptability in the north also, as there is acceptability in the south.

We are not for confrontation because that is not the essence of it. We have never worked for any confrontation. We are for cooperation and for solving this basic problem. Therefore, I would make an appeal to the Home Minister that at this crucial stage of the debate he must come forward and throw some light on this, that we are moving forward and, I hope, that some positive statement will come from him.

15.09 hrs.

[SHRI R.S. SPARROW *in the Chair*]

Mr. CHAIRMAN : Now, the House must appreciate that we have to close the debate at 3.30. P.M.

SOME HON. MEMBERS : The time may be extended.

श्री रामविलास पासवान : सभापति जी, मुझे आप से एक निवेदन करना है । स्पीकर साहब ने कल रूलिंग दी थी कि 12 बजे के बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर डिबेट शुरू की जायगी और वह साढ़े तीन बजे तक खत्म हो जानी चाहिये । उस के बाद प्राइवेट मेम्बर्स के बिल लिये जायेंगे । दुर्भाग्य से यह डिबेट 12 बज कर 50 मिनट पर शुरू हुई, हम शुरू से ही 50 मिनिट लेट हो गये । मेरा निवेदन है कि इसके लिये एक घन्टे का समय बढ़ा दिया जाय और उस के बाद प्राइवेट मेम्बर्स का बिजनेश शुरू हो जो 7 बजे तक चले । इससे सब लोगों को एडजस्ट किया जा सकेगा ।

SHRI CHANDRAJIT YADAV : It is a good suggestion. You may accept it.

MR. CHAIRMAN : We will look into it.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : May I suggest that one hour more may be given for this discussion and then we can switch over to Private Members Business and then to the Legislative Business ?

MR. CHAIRMAN : I will confirm this when the Minister for Parliamentary Affairs comes.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Don't be so late. Why do you postpone it ? The Minister for Home Affairs himself has made the proposal.

MR. CHAIRMAN : If the whole House feels that way.....

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I seek a clarification. If this debate continues up to one hour, then will the Private Members Business be taken up ?

MR. CHAIRMAN : At 4.30 PM.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Then it will continue up to 7.00 PM, 2 1/2 hours will be allotted for Private Members Business.

MR. CHAIRMAN : Yes. The only stipulation is that at 7.00 PM the Government Business will have to be taken up. On that we agree.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Baramulla) : I will speak in Kashmiri language. There is a reason for that. I took the oath on 25th July in Kashmiri language but the Circular showed that somebody else has taken the oath in Kashmiri language. Thereafter, I have been trying my best to speak in Kashmiri language but there was no arrangement for interpretor. Thanks that one is arranged for me today. It is my luck to speak in Kashmiri. Kashmiri is a rich language.

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : काश्मीरी संविधान में मान्यता प्राप्त लेंगुएज नहीं है। (व्यवधान) आप संस्कृत में बोलिये।

PROF. SAIFUD--DIN : It is included in the VIII Schedule of the Constitution among the 14 national languages.

It is my privilege that I am the first Member of Parliament to deliver speech for the first time in Lok Sabha in Kashmiri language.

MR. CHAIRMAN : It may not be possible for me to know when I should ask you to conclude. Kindly keep the time in mind.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Barmulla): Sir, the Mandal Commission has made very useful recommendations about backward classes which is quite a laudable measure. It is true that we have to evolve a society in India where ultimately merit alone should count. But so long as there are some backward sections of population, it is necessary that we must have reservations. The Mandal Commission has rightly stated that the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes constitute 22.5% of our population, whereas other backward classes come to about 52%. But since the Supreme Court has given several judgments in various cases pertaining to J & K and other States where they have said that reservation should not exceed 50%, the Mandal Commissions have rightly recommeded 27% reservation for other back ward classes, They had observed that the reservation should not exceed 50% of the

*The original Speech was delivered in Kashmiri.

total. population. The Mandal Commission had to arrive at that conclusion because they felt that mont of the posts in Government departments public sector undertakings and admissions in colleges and universitities and technical institutions have been taken by the richer or advanced sections of the population. The sooner the Government accepts the Mandal Commission's broad recommendations the better for the country.

Sir, I would like to give the implications of Mandal Commissions' ecommendations with regard to J & K State. The State has three regions, Ladakh, Jammu and Kashmir. About 75% of the population of both Jammu and Kashmir regions been deprived of the benefits available to ST/SC. Perhaps Scheduled castes in Jammu region are getting their share of benefits; there is no objection to it. But since there are no Scheduled Castes among the Muslims, population of Kashmir valley have automatically been deprived of the benefits that go normally to Scheduled Castes and Scheduled tribes. That is against spirit of the the Constitution of India. A speical Committee was set up by the J & K Government under the Chairmanship of Justice Jankinath Wazir to determine the socially backward classes. Earlier to that the Gajendragadkar Commission had recommended that a high-powered Committee should be appointed for that purpose. Wazir Committee has demarcated certain social castes which carry similar stigma as is carried by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in other parts of India. In this connection I am sorry to state that the Mandal Commission has not been able to take note of the social castes which could be covered by their reeommendations. The Mandal Comission itself had suggested on page 6 that fishermen and banjaras, khatiks etc. carry stigma of untouchability in the country. They have been listed as OBC by the Commission. Their inclusion in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been recommended and it may be considered by the Government Whereas the Mandal Commission had made this recommendation they forgot to give the same benefits to the social castes in J & K, as are given to Scheduled Castes. A similar mistake was committed by the Commission in U. P. as well ; that also should be looked into. Whereas Hindu Gujjars were included in the list, the Muslim Gujjars were not included although they are as backward as Hindu Gujjars. Similar mistake has been committed with regard to J. & K.

Sir, there is another matter which is equally important. There are many regions in that State of J & K which are very backward, which are inaccessible for most of the time in winter There are no roads, no air links etc. there and they continue to remain very backward. That is why our Government had adopted a multiple criteria for determining the backwardness of these areas and they had requested the Government of India to declare them backward but the Central Government is not quite clear on this issue So far as the State Government is concerned, it had asked for granting of Scheduled tribe status to Ladakh but at the same time it had stated that other areas like Gurez, Karneh Keran, in Uri in Kashmir region and Bani, Dudu, Basantgarh, Mahoor, March and Mendhar in Jammu region too should also be included in STICS. But ever since the State Government has made these recommendations, the Central Government has given least attention to this problem. I feel the State Government is quite clear on this point but the Central is not. Ladakh should be given the scheduled Tribe status but other areas too should be given the same status. We have no confusion in our mind on this.

The Mandal Commission has not made any special recommendations with regard to our State whether it was the question of socially backward class or backward areas. But the Commission has made a reference and that is about Gujjars. But Gujjars are not the only caste, to be enlisted. There are Bakarwals and others also. Therefore, the only solution is that multiple criteria should be adopted for determination of backwardness of such castes and thereafter they should be declared backward classes.

Sir, Mandal Commission's recommendations could not be uniformly applied to a vast country like India. There are different States with different problems. But I fee

that Mandal Commission is providing a set of workable guidelines in this regard. The Government of India should understand the sprit of the recommendations of the Commission and should implement them in the same spirit. If we have to make this country great and have to put it on the path of progress and emancipation then we must appreciate the spirit of Mandal Commission's recommedations. In the end I would like to submit, Sir, one thing. I doubt whether the members occupying the Treasury Benches have really gone into the details of the Mandal Commission's Report. Therefore, I would like to suggest that the Hon. Speaker should organise a seminar which should debate the Commission's recommendations in detail. I would also request the Hon. Members belonging to ruling party to study the recommendations of the Commission in depth. If they implement them sincerely they can really do good to this country and its people.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति महोदय, यह जो लड़ाई हो रही है वह गरीब और अमीर की लड़ाई है ।

It is a struggle of Have and Have-nots.

महात्मा गांधी ने हमारे लिये यह लिखा है—

> "Swaraj is a meaningless term, if we desire to keep a fifth of India under perpetual subjection, and deliberately deny to them the fruits of national culture We are seeking the aid of God in this great purifying movement, but we deny to the most deserving among His creatures the rights of inhumanity. In human ourselves, we may not plead before the throne for deliverance from the inhumanity of others."

यह चीज है जिसकी वजह से हम महात्मा गांधी के साथ हैं । इस वजह से हमने डा० अम्बेडकर की बात नहीं मानी और महात्मा गांधी की बात मानी । डा० अंबेडकर ने कहा था कि हिन्दुस्तान को तकसीम कर लो । हमने उनकी बात नहीं मानी और महात्मा गांधी की बात मानी । "That without which we cannot live must come on to us."

पासवान जी कहते हैं कि वहां पर यादव ज्यादा हैं । यादव बैकवर्ड हैं । मैं आपको बताऊं कि बाबू जगजीवन राम ने कितने आदमियों को जमीन दिलाई है । मैंने पंडित जवाहरलाल से मिलकर गरीबों को जमीन दिलाई थी । उस वक्त भीम सैन सच्चर ने कहा था कि मिनिस्ट्री ले लो । मैंने कहा कि मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, जमीन चाहिए । जमीन की बात करो । उसने जबाब दिया : मैं नौकरी देने के लिए तैयार हूं लेकिन जमीन मैं नहीं दे सकता हूं । यह इस वास्ते कि जिनके पास जमीन है वे स्ट्रांग हैं और जो लेने वाले हैं वे कमजोर हैं । इस वास्ते इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता । मैं जवाहरलाल जी से मिला । उन्होंने भीम सैन सच्चर को रगड़ा चढ़ाया । फिर जाकर हमें जमीन मिली । दो लाख एकड़ जमीन इस तरह से पंजाब और हरियाणा में लोगों को मिली । हमारे यहां बीस बीस आदमी कत्ल एक-एक बार मे नहीं होते हैं जैसे आपके यहां होते हैं । हमारे यहां स्ट्रांग आदमी हैं । कहीं बात पर भी मुकाबला करके देख लो । आप क्या कर रहे हो ? एम० एल० ए० और एम० पी० बनकर आ जाते हो और आपके यहां बीस बीस आदमी कत्ल कर दिये जाते हैं । क्यों नहीं आप भी लड़ते ? मांगने से कुछ नहीं मिलता । मांगना बन्द कर दो । लड़कर लो ।

यह कहा जाता है कि लैंड रिफार्म्ज पर अमल नहीं हुआ है । मैं कहता हूं कि कोई नहीं करेगा । मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं यह मान भी लें तब भी नहीं चलेंगी । इनका

अमल नहीं होगा। ये करेंगे ? हमारे हाथ में तभी कुछ आएगा तो हम कुछ करेंगे। स्वामी विवेकानन्द ते कहा था :—

> "Him I call a Mahatma whose heart bleeds for the poor otherwise he is Duratma."

जातपात की बात नहीं है। गरीब आदमी के लिए जो लड़ाई करता है वह आगे बढ़ जाता है। इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। इसमें हिन्दू सिख का कोई सवाल नहीं है। जो लड़ाई गरीवों के लिए करता है वह कामयाव होता है। सी०पी०एम०, सी०पी आई० या कांग्रेस हर पार्टी मे अच्छे आदमी भी हैं, बुरे भी हैं। जो सीधा परमात्मा से ताल्लुक रखता है, वह लड़ाई करता है तो कामयाब होता है।

अम्वेडकर मिनिस्ट्री छोड़कर आ गया था। मैंने कहा कि आप क्या कर लेंगे, दो मिनिस्टर थे और एक छोड़कर आ गया है। मैंने कहा कि तुम ने गलती की है। अब तुम लड़ाई नहीं कर सकते। कहने लगे कि मैं पाजामा कुर्ता खद्दर का पहनता हूं फिर भी जवाहरलाल नेहरू मेरे से बात नहीं करता है। मैंने कहा कि मैं करवाऊंगा, लेकिन बेचारा मर गया। उसकी आप पूजा करते हैं। आदमी में लड़ाई करने का दम होना चाहिये। लेक्चर से कुछ नहीं होता कुछ करने से होता है।

"अमल से दुनिया बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी

यह खाकीं अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है"

> "It is not the number of fighters that counts. It is the quality of which they are made which becomes the deciding factor" The great man of the world always stood alone.
>
> M.K. Gandhi

नम्बर से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी से होता है। एक आदमी लड़ाई करता है और दुनिया को या कम्युनिटी को फायदा होता है। महात्मा गांधी ने लड़ाई की, तमाम दुनिया को आजाद करवा दिया। इसी वास्ते मेरे मन में उनके वास्ते इतनी इज्जत है, कद्र है और मैं उनकी पूजा करता हूं और उनकी किताबें तकसीम करता हू। उनके सिवाय मुझे कोई नजर नहीं आता है। इतना शानदार आदमी था कि सबको डिफीट देकर आगे निकल गया। इसलिए मैं उसका फालोअर हूं।

अपोजीशनन ठीक हो तो हम भी ठीक हो जाएंगे। वह ठीक नहीं तो हम क्या करें। जमींदार कभी जमीन नहीं देगा। अपने भाई को नही देता तो आपको क्या देगा। अपना हक लेने वास्ते लड़ाई करनी होगी। जो कमजोर हैं अगर वह नहीं ले सकता है तो इसमें जमींदार का कोई कसूर नही है।

विवेकानंद ने कहा था :—

> "To be a good dear and believe that we are selected by the Lord to do great things and we will dc them Hold yourself in readiness That is. Be pure and holy anc love for love sake. Love the poor the miserable, the down-trodder and God will bless you."

आपको अपने आप को ठीक करना है, किसी और को ठीक नहीं करना है जिसकी मौजूदगी में ऐसे हालात हो रहे हैं, वह क्यों नहीं लड़ाई करते हैं ? मैं आपको एक शेर सुनाता हूं—

मेरी अब जिन्दगी को ठोकरें खाना नही आता,
मैं मजबूरे तमन्ना हूं कि मर जाना नहीं आता,
हवासो होश खो कर, दिल को समझाना नहीं आता,

पर ये दुनिया अपनी दुनिया है, हम ही तो इसके मालिक हैं,

कोई बेगाने के घर में कोई बेगाना नहीं आता ।

ये 100 आदमी यहां बैठे है—

तेरे मस्तीं को साकी शोरे महशर क्या उठायेगा,
ये वो हैं जिनको पीकर होश में आना नहीं आता

श्री आर०एन० राकेश (चैल) : सभापति महोदय, मैं कुछ कहूं, इससे पहले मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने भी मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया है और उसे तुरन्त लागू किये जाने की मांग की है ।

मैं सदन की उस भावना का आदर करता हूं जो कहते हैं कि भूख इंसान में होती है, जाति, बिरादरी, धर्म और मजहब में भूख का रंग अलग-अलग नहीं होता । लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो ऐसी भावना रखते हैं कि मनु-स्मृति की रचना के समय भी तो भूख थी और उस भूख का रंग भी तो यही था जो आज है । बाल्मीकि रामायण के समय शम्बूक ऋषि के वध के समय भी भूख का रंग यही था जो आज है । महाभारत में छल, कपट और प्रपंच के द्वारा एकलव्य के अगूठे को कटवा लिया गया भी भूख का कोई और रंग नही लाया । तुलसी की रामायण में रामचन्द्र जी का राज-तिलक होने के समय महान पौरुषधारी विश्वामित्र को इसलिये राजगुरु नहीं बनाया गया कि वह एक जाति विशेष के नहीं थे । आप कह सकते हैं कि ये बातें पुरानी है आज मौजूदा हालत में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं ?

अभी मेरे साथियों ने श्री राम विलास पासवान ने भी पं० जवाहरलाल नेहरू की स्पीच को कोट किया । मैं उस स्पीच से सहमत हूं, और उसका आदर करता हूं, लेकिन जब वे भारत के प्रधान मत्री बने तो मिथिला ब्राह्मण, काशी के ब्राह्मण और दक्षिण भारत के ब्राह्मण पीछे की लाईन में चले गये और काश्मीर के ब्राह्मण आगे आ गये । कहने का मतलब यह है कि जातिवाद व्यवस्था इतनी तीव्र रही कि जो इकनामिकली, सोशली, एजूकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, मंडल कमीशन ने उनका समर्थन किया । अब 36-37 वर्षों की हुकूमत ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट में काका कालेलकर की रिपोर्ट को, जनता पार्टी जो 3 साल की थी, उसने उसे दफना दिया । लेकिन मैं उसका अभारी हूं कि उसने मंडल कमीशन को जन्म दिया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आज हम इस मंच से सदियों से चली आ रही परंपराओं, जातिवादी व्यवस्था और इन्सान को ऊंचा-नीचा समझने की परिपाटी को दफना कर इन्सान को इन्सानी हुकूक दिलाने की माग कर रहे हैं ।

गुजरात आरक्षण के बाद जो आग वहां लगी थी, उसके बारे में भारत की प्रधान मंत्री ने बयान दिया था कि मैं आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन मेरिट की हत्या नहीं होगी, जिसका मतलब यह है कि मैं हरिजनों की हमदर्द हू, लेकिन मै हरिजनो के हत्यारो को सजा नहीं दूंगी । इन बातों से पता चलता है कि अभी तक इस सरकार की नीयत क्या रही है । सारे देश के आरक्षण-समर्थक सरकार की इस मशा को समझ चुके है ।

लेकिन आज पक्ष और विपक्ष, इधर और ऊधर बैठे हुए अधिकांश लोगों की भावनाएं

मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि आज यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।

डा० अम्बेदकर दूर-द्रष्टा थे। वह कहते थे कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज एक सिक्के के दो पहलू हैं, वे दोनों वर्ण-व्यवस्था के गुलाम हैं : एक भीतर का गुलाम है, दूसरा बाहर का गुलाम है, एक चिलम-चढ़वा गुलाम है, तो दूसरा पानी-भरवा गुलाम है और जब तक सब गुलामों को मुक्ति नहीं मिल सकेगी, तब तक समाज में बराबरी कायम नहीं हो सकती, समान अवसर की बात नहीं उठाई जा सकती। डा० अम्बेडकर ने इसी आधार पर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन हमने उसको इस रूप में स्वीकार नहीं किया। दुर्भाग्य इस बात का है कि यदि डा० अम्बेडकर को डा० लोहिया को, सरदार बल्लभभाई पटेल को या रफी अहमद किदवई को भारत का प्रधान मंत्री बनने का मौका मिला होता, तो आज हमें इस बदनीयत सरकार से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने की भीख मांगनी पड़ती। (**व्यवधान**) डा० अम्बेडकर शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और बैकवर्ड क्लासिज के लिए सम्पूर्ण आरक्षण की बात करते थे। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को आरक्षण मिला हुआ है, जबकि बैकवर्ड क्लासिज आरक्षण के लिए बड़ी कातर दृष्टि से इस सदन की ओर देख रही है। एक पहलू को आरक्षण मिला हुआ है, दूसरे को नहीं। जब तक दोनों पहलुओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक आरक्षण की व्यवस्था पूरी नहीं, अधूरी है, आंशिक है। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से संपूर्ण आरक्षण की मांग करता हूं।

चूंकि समय कम है, इसलिए मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि "सताए जो पिछड़ों को, उसे शैतान कहते है, उठाए जो पिछड़ों को, उसे भगवान् कहते हैं।" इस सरकार का इरादा क्या है, इसका फैसला तो वह करे। लेकिन यह तो आउट-गोइंग गवर्नमेंट है। सेठी साहब को मेरी नेक राय है कि जाते जाते वह क्रेडिट ले लें और इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें। इतिहास रहेगा, इतिहास में उनका नाम रहेगा। सरकारें तो आती-जाती हैं, इसके लिए उन्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए वह न रोएं। वह जा रहे है, लेकिन वह इसका क्रेडिट ले लें।

मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तत्काल इम्प्लीमेंटेशन की मांग करता हूं और आशा करता हूं कि यह सरकार इसमें हीला-हवाला नहीं करेगी। इसके चार साल तो बीत गए और दो-चार महीने की बात है। वह इस रिपोर्ट की इम्प्लीमेंट कर दे, अन्यथा हमें इसके लिए इनकमिंग गवर्नमेंट के सामने जाना ही पड़ेगा।

जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में इस सदन में बात उठी है, तो इस बारे में सरकार का रेडियो और टी.वी. चुप है। अखबारों में पूरी बात नहीं जाती है, सैंसर हो जाती है। हिन्दुस्तान की जो 80 प्रतिशत जनता है, उसकी यह मांग है कि यदि सही अर्थ में हिन्दुस्तान को आजादी देने की बात है, तो इन खबरों का प्रसारण पूरी तरह से होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः मंडल आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI D.K. NAIKAR (Dharwad North) : When this Mandal Commission report was submitted and placed on the Table of the House, at that time I had participated in the discussion. I had also made my submission in detail. Some of the constitutional provisions were also explained by me.

Much has been said on the Mandal Commission report, and its non-implemen-

tation by the Government. In my humble opinion, it is not a policy to be determined by the Government after hearing the views of the Members of of this House. Every one of us has taken an oath under the Constitution to maintain the provisions of the Constitution. So, it is the duty of the Government to uphold the Constitution; and whatever obligations have been created under the Constitution, must be discharged by the Government itself. Under the Constitution, it is very clear : a Commission should be appointed under Article 340 to investigate the living conditions of the people who are socially and educationally backward. Then they must make a recommendation about the grants - even some of the concessions to be given under the Constitution under Articles 15(4) and 16(4).

Much controversy has been raised in this country on accont of these two concessions. I must make it very clear as to what are the concessions that these so called backward classes are getting under these two clauses. Article 15(4) says that the State can make any provision for the advancement of any socially and educationally backward classes.

Socially and educationally backward classes have to be identified by the Commisison appointed underArticle 340. So, without the appointment of a commission, you cannot identify who are socially and educationally backward in this country. Now this is a concession under Article 15(4). What are the provisions for the advancement of socially and educationally backward classes, if caste is taken as a criterion ? Upto this day, according to my, personal experience, no grants have been made in favour of any socially and educationally backward people on the basis of caste. So, in my opinion, even though we have implemented, in Karnataka, the L.G. Havanur Commission's report, nothing has been done so far as Article 15(4) is concerned.

Now about Article 16(4) i.e. about the question of reservation in the matter of puplic employment. So, the very crucial point is : where is the question of reservation, without ascertaining whether there is adequate representation in employment? The question of reservation would arise only when the Government feels that a particular class or community does not have adequate representation in Government services.

My friends said that economic criterion should be adopted in reservation. There is a question : on an economic basis, you cannot ascertain it. I may say that the caste should be the criterion to ascertain whether there is an adequate representation in Government employment or not. In this context, you may see Article 15(4). But Article 15(1) is also there, which says : "The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them." But Article 15(4) is an exception to the main provision. Even if, on caste basis, reservation is made, it does not come under discrimination under the meaning of Article 15(1).

That is one of the spirits that has been carried under the Constitution. Similarly, Article 16 says no discrimination in the matter of public appointment, equality of opportunity in the appointment. Even then in cases where adequate representation is not there, if we make caste as the criterion, then there is no question of discrimination even under Article (6) also. I am afraid, even till today, whether anybody can ascertain a criterion whether there is adequate representation or not; if not, the caste it is only the caste which can be taken into consideration while ascertaining whether adequate representation is there in public service or not. On this basis only you can make the reservation.

If a class of people is there, caste business is already there; and every State has accepted it. I do not know why so many difficulties have come before the Central Government also. What i sprovided und er the Constitution should be interpreted in your wisdom and you should take a decision; it cannot be debated on any account either this way or that way, attacking one community, degrading another community. It is not a question of war between caste and community. It is only a

question of adequate representation to service. If there is no adequate representation, there is no question of reservation at all. This is a small concession for these socially and educationally backward people; and they will not take away anything. It varies from State to State. Even in Karnataka, we have made reservation of 58 per cent; because my friend said that it should be 50 per cent only, I may quote an example. If Arunachal Pradesh, if the total population of backward classes is 80 per cent, if we make a reservation of 50 per cent, then reservation would be for those 20 per cent and not for 80 per cent. Therefore, reservation should be to the extent of the total population that exists in a particular State. Therefore, it varies from State to State, not a general guideline. Therefore, reservation, the State Government's discretion should be taken into account. Therefore, what has been recommended by the Mandal Commission Report, in my humble opinion, is in tune with the provisions of the Constitution; is in pursuance of the provisions of the Contitution; and that the obligation created on the part of the governmen; should be discharged. The government has alreay taken the views of the members in this connection. I don't think there will be any difficulty on this. I thank you very much for giving me an opportunity to speak.

MR. CHAIRMAN : To respect the decision take by the House, the debate should close sharply at 4.45 P.M. After that the Hon. Minister will reply. So, I request all of you to take minimum of time.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, इस मुल्क को आजाद हुए करीब 36 वर्ष हो गये हैं लेकिन फिर भी जनतन्त्र का सही प्रतिविम्ब नजर नहीं आता । इस मुल्क में प्रशासन में जाने का आधार वोट और 52 प्रतिशत लोग इस मुल्क में बैकवर्ड क्लासिज के हैं, साढ़े बाईस प्रतिशत शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, 11 प्रतिशत माइनारिटीज हैं, इन लोगों को मिलाकर 86 प्रतिशत होता है, ये 86 प्रतिशत लोग इस दौर में पीछे छूट गये और 14 प्रतिशत लोग अपनी धुर्तताई से आगे बढ़ गये । इस मुल्क के करीब 90 प्रतिशत के हाथ में 10 प्रतिशत वेल्थ है और 10 प्रतिशत के हाथ मे 90 प्रतिशत वेल्थ चली गई है । इन बातों की परिकल्पना करके संविधान के निर्माताओं ने संविधान मे यह व्यवस्था की थी कि जो इस जिन्दगी के दौर में पीछे छूट जायेंगे उनके लिए आरक्षण किया जायेगा । पहला बैकवर्ड क्लासिस कमीशन 1953 मे बना जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी, लेकिन वह रिपोर्ट इस सदन का मुंह नहीं देख पाई । दूसरा बैकवर्ड क्लासिस कमीशन स्वर्गीय श्री बी०पी० मंडल जी की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को बना और उसने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 को दी । उसमें टर्म्स आफ रेफ्रेन्स ये थे :

"आयोग को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप स पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने और उनकी प्रगति के लिए किये जाने वाले उपायों की सिफारिश करने तथा ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जिनका संघ या राज्यों की सेवाओं और पदों से आरक्षण की व्यवस्था करने की वांछनीयता अथवा अन्यथा की जांच करने के लिए कहा गया था ।"

ये टर्म्स आफ रेफ्रेन्स थे । कमीशन ने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करके और सरकारी आँकड़े लेकर तथा विभिन्न संगठनों से बात करके अपनी रिपोर्ट दी है और आयोग ने 3743 अन्य पिछड़े वर्गों की सूची दी है और इसके मुताबिक अनुमान करके बताया है कि यह देश की कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत है ।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो अनुशंसा की है, उसमें यह कहा गया है :

"आयोग ने सिफारिश की है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था न केवल सरकारी सेवाओं और सरकारी प्रतिष्ठानों में ही की जाए बल्कि निजी क्षेत्र के उन प्रतिष्ठानों में भी की जाए जो सरकार से वितीय सहायता ले रहे हों। शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण की सिफारिश की गई है। आयोग ने कुछ अन्य सिफारिशें भी की हैं, जो शैक्षिक रियायतें और सुविधाएं तथा वितीय सहायता देने के बारे में हैं।

सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि 14 महीने गुजर जाने के बावजूद भी सरकार ने सदन के पटल पर उस रिपोर्ट को नहीं रखा था। यद्यपि यह संवैधानिक आवश्यकता है कि इस तरह की रिपोर्ट के साथ-साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट भी रखी जाती है लेकिन जब हमने इस बात के लिए बहुत जद्दोजहद की और सरकार को बहुत प्रेसेराइज किया तो 14 महीने के बाद 30-4-83 को सदन पटल पर उसको रखा एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में केवल यही बताया कि केन्द्रीय सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को विभिन्न राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए उन्हें भेजा है। यह उन्होंने कहा और उसके बाद वह चुप हो गई। हमने बार-बार यह बात यहां सदन में उठाई, तो उसके बाद मुख्य मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई गई लेकिन मुख्य मंत्रियों में से किसने उसका विरोध किया और किसने उसका समर्थन किया, बार-बार सदन में इस बात को पूछा गया ताकि कोई मीनिंगफुल डिस्कशन हो सके लेकिन आज तक वह बात नहीं आ सकी है। हम लोगों की जानकारी के मुताबिक ज्यादातर राज्य सरकारों ने इसका समर्थन किया है और जिन लोगों ने विरोध किया था जैसे पहले विहार ने विरोध किया था लेकिन बाद में संशोधित करके उसने केन्द्रीय सरकार से इसको मानने की अनुशंसा की और इसको लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा कि हम इसको मानते हैं तो आज मुल्क में बड़े पैमाने पर इस तरह का एक माहौल बन रहा है विभिन्न राज्यों में और खास कर केन्द्रीय सरकार पर इस बात का जोर पड़ रहा है कि वास्तव में मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन्स हैं, उनको माना जाए।

मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन मुख्यतः यह है कि 27 परसेन्ट रिजर्वेशन होना चाहिए। अब 27 परसेन्ट रिजर्वेशन इन लोगों को देने की बात आती है और हमने जब सदन में इस बात को उठाया तो सरकार की तरफ से जवाब आया अभी अप्रैल 198: में कि हमने सैक्रेटरीज की एक टैक्नीकल कमेटी बना दी है और वह बताएगी कि कहां क्या स्थिति है और किस राज्य में क्या होना चाहिए और यह जो रिपोर्ट है इसमें कुछ एड करने की जरूरत है या कुछ सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत है। 3 महीने का समय उसे दिया गया था और वह समय गुजर गया है लेकिन आज तक सरकार ने उसके बारे में नहीं बताया है कि उसने क्या किया है। दरअसल में सरकार यह साफ नहीं कहना चाहती है कि वह इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है या नहीं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पहले भी और अब जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें दोनों तरफ लोग इस बात पर यूनेनीमस हैं कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन्स को तुरन्त इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी हमारे और भी साथी इस पर बोलेगें और उनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सब इस बात पर यूनेनीमस हैं कि रिकमेंडेशन्स को इमीजियेटली इम्प्लीमेंट किया जाए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको अविलम्ब माना जाए।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि वास्तव में कुछ भ्रान्ति फैलाई जाती है और यह

कहा जाता है कि यदि 27 परसेन्ट रिजर्वेशन दे भी दिया गया तो क्या वास्तव में इससे एम्पलायमेंट का सवाल हल हो जाएगा। हम कतई नहीं कहते हैं कि इससे यह सवाल हल होगा। लेकिन इतना हम अवश्य मानते हैं कि उनका सोशल सेक्शन होगा, उनको यह लगेगा कि वे भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब किसी हरिजन या बैकवर्ड क्लास का कोई डी०एम० या एस०पी० होगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा कि कम-से-कम हमारी सही बात तो कोई सुनने या मानने वाला है।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं रिजर्वेशन देने से एफीशियेन्सी घटेगी जो यह अक्सर कहा जाता है, उसके उत्तर में मैं आपको कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु में 68 परसेंट रिजर्वेशन है। यह सरकारी आंकड़े बताते हैं। उसके बाद भी तमिलनाडु इज द बेस्ट एड-मनिस्टर्ड स्टेट। यह कैसे बेस्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट है ?

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस बात की अविलम्ब घोषणा करे कि वह मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मानती है और सरकारी मिडिया में और पेपर्स में वह इसको ड्यु इम्पार्टस दे। यही देश के दृष्टिकोण से अच्छा होगा।

15.56 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

श्री जयराम वर्मा (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष, जी, हमारे समाज में पिछड़े हुए वर्गों का विशाल समाज है। उनकी आबादी 52 प्रतिशत है। उनके अतिरिक्त 22-1/2 परसेंट लोग शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। इस तरह से पिछड़े हुए लोगों की कुल आबादी हमारे देश में 74 या 74-1/2 प्रतिशत होती है। विभिन्न धर्मो और सम्प्रदायों में जो उन्नत वर्ग के लोग हैं उनकी कुल संख्या केवल 25-1/2 प्रतिशत होती है।

श्रीमन् किसी देश में अगर 74-1/2 प्रतिशत लोग शक्ति के क्षेत्र से बाहर रह जाएं, शासन में उनका इन्वालवमेंट न हो तो फिर यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि वह शासन या जनतंत्र ठीक ढंग से चल रहा है। इसलिए जनतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि देश के सभी वर्गों और समुदायों का उसमें इन्वालवमेंट हो। यह जरूरी है कि सरकारी सेवाओं में सभी लोगों का हिस्सा हो। तभी जाकर जनतंत्र मजबूत हो सकता है और तभी जाकर देश आगे बढ़ सकता है, देश का कल्याण हो सकता है। तभी जाकर देश को आगे बढ़ाने की रफ्तार भी तेज हो सकती है। जब तक वर्तमान स्थिति कायम रहती है तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि सही मायनों में जनतंत्र की जड़े मजबूत हो गई हैं। तब तक यह नहीं कहा जा सकेगा कि देश को आगे बढ़ाने की रफ्तार तेज करना संभव हो सकेगा।

जब तक अधिकतर लोग जो पिछड़े हुए हैं, उनको वास्तव में आगे न लाया जाए, उनके लिए ऐसी व्यवस्था न की जाए कि उनके अन्दर जो छिपी हुई प्रतिभा है, उसको विकसित कर उनको इस योग्य बना दिया जाए कि वे अपनी पूरी शक्ति के साथ देश की सेवा में लग सकें तब तक विकास करने की रफ्तार को तेज करना संभव नहीं होगा। इस पूरी आबादी को हमें देश सेवा में और देश के विकास के कार्यो में लगाना है और इसी से हम सचमुच प्रगति कर सकेंगे और कह सकेंगे कि हमने प्रगति की है।

इन बातों को महसूस करके ही, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने यह ठीक समझा कि देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को उपेक्षित रखना ठीक नहीं होगा। इसकी व्यवस्था के लिए ही संविधान में पिछड़े हुए लोगों के लिए आर्टिकल 340 रखा गया, जिससे कि राष्ट्रपति उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए कमीशन नियुक्त करें। संविधान में अनुच्छेद 16 (4) ऐसे लोगों के लिए है जिनका सरकारी सेवाओं में बहुत कम स्थान है और सरकार उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सके। लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी। शिक्षा के बारे में और दूसरी सुविधाओं के बारे में कमी को संविधान में आर्टिकल 15 (4) को जोड़ कर दूर किया गया।

जब यह मंडल कमीशन नियुक्त हुआ तो मुख्य रूप से उसके सामने दो विचारणीय प्रश्न थे।

16.00 hrs.

एक प्रश्न यह था कि जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं उनके वर्गीकरण का आधार क्या होना चाहिए दूसरा उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए इस कमीशन ने पूरे देश का दौरा किया आब्जेक्टिव टेस्ट लगाकर इस नतीजे पर पहुंचा है कि देश में जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो शहरों से दूर रहती है, जिनके पेशों की आमदनी बहुत कम है और सरकारी सेवाओं में जिनका स्थान बहुत कम है, उनका शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो के वर्गीकरण का आधार मानना ठीक होगा। उन्होंने इसको आधार माना और इसके लिए सिफारिशें की।

रिपोर्ट को आए हुए काफी दिन हो गए हैं। स्वाभाविक है कि इसको लेकर लोगों में असंतोष हो। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सिफारिशों को किस तरह से लागू किया जाए जिससे इसका अच्छे से अच्छा असर पड़े और देश की तरक्की हो, इसलिए समय लग सकता है। इसमें समय लगना स्वभाविक है। इसके लिए अधीर नहीं होना चाहिए।

एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी नेता इंदिरा जी बैकवर्ड क्लासेज की बहुत बड़ी हमदर्द हैं। वे बड़ी दिलेर नेता हैं। वे बहुत साहस से काम कर सकती हैं। वे किसी भी काम के लिए बहादुरी से कदम उठा सकती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी स्थिति में वे हिम्मत से और बहादुरी से काम लेंगी और सारे समाज को उठाने के लिए, देश की हालत को सुधारने के लिए और प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए मण्डल कमीशन की सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार करेंगी और इस देश में सही माइने में प्रजातंत्र कायम करेंगी। जैसा कि कहा गया है कि "वीर भोग्या वसुन्धरा"

"The brave rule the Earth"

वे बहादुर है, उनमें हिम्मत है। वे सचमुच में इस देश में सही व्यवस्था कर सकती हैं। हमें उनमें विश्वास है कि उनकी सरकार, होम मिनिस्ट्री ऐसा काम करेगी जिससे लोगों में जो निराशा है वह दूर हो। आज मंत्री महोदय ऐसा बयान देंगे जिससे लोगों की आशा पूरी हो।

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh): Sir, there had been rare occasions in this House when there had been total unanimity on any subject, such as on the recommendations of the Mandal Commission. This is the third occasion when we are discussing the recommendations of the B.P. Mandal Backward Classes Commission. Whether the speech is from the ruling party

or from the opposition, I do not think there is any difference. There is complete unanimity and total identification in the approach. This is the consensus, the unanimous opinion of the House. I fail to understand why the Government do not pay heed to this unanimous opinion of this House.

I would like to know from the Home Minister today what his problems are and why he is not coming forward to accept the principle of reservation, because the principles of reservation are not questioned today. They are part of the Indian Constitution. We have given certain reservations to the most neglected, the weaker sections of our society, our brothers and sisters belonging to the Scheduled Castes and Tribes. They are given reservation and that is part of our Constitution today.

For the other backward classes also there is reservation in the majority of the Indian States today and in almost all the States in the South, and many States in the north. The reservation in the State service varies from 20 per cent to 68 per cent.

Therefore, even for the backward classes the principle today is not the question. It is already accepted. The question today is : What is agitating the mind of the entire weaker Section of the society ? India is being ruled by your Central Government officers, IAS, IPS and other officers sitting in the Secretariat either at Delhi or in State capitals. Bureaucracy is a very important effective instrument for implementation of policies and programmes and there, there is no representation of 80 per cent of the population of this country, and that is the crux of the situation.

I would request the Home Minister to read carefully the speech of Pandit Jawaharlal Nehru delivered on 29th May, 1951, when he himself moved the First Amendment to the Indian Constitution when the reservation in Tamil Nadu was struck down by the Supreme Court. When Panditji was visiting Madras, E.V. Ramaswamy Naicker. with lakhs of people went to demonstrate against him and he said, 'this important right has been taken away. from the backward classes people'.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would put the record straight. E.V. Ramaswamy Naicker led a deputation and met Vallabhai Patel.

(*Interruptions*).

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Yes. And Pandit Jawaharlal Nehru saw the justification and he came and delivered a speech in the Select Committee and also in the Parliament. Sir, I am not going to quote many things, but what Panditji said then, perhaps today that is the situation also in the South.

Panditji said : "I think I may say with perfect truth that every single member of the Select Committee recognised the desirability of giving these opportunities for growth to those who, in a sense, may be considered backward"-"every Member of the Select Committee," and today every Member of this Parliament. Then, I would like to know what are the difficulties.

Two years and 9 months have passed since the submission of the B.P. Mandal Commission Report. Thirty-three years before, the Constitution came into existence. Now a feeling is growingthat the Government is not serious, the Government is under the pressure of the status quoist section of the society, the Gooernment does not want to bring socio-economic development in the society and therefore, the Government is being pressurised by the vested interests which do not want to give up their right to rule in this country. That is the problem. I would like the Home Minister to reply to this question.

Sir, the Chief Ministers' Conference was called after that. There is a lot of mass agitation going on, people are speaking; the Congressmen, people outside the Congress Party, the Opposition Parties are all agitating. Thirteen Leaders of Opposition parties issued a joint statement. Today all members of the Congress Party are speaking with one voice with the Opposition members There is no difference on this. Then, why does not the Government take the decision ?

Let the Home Minister tell us his difficulties. I am interested in knowing his difficulties. If we can help in finding out a solution, we will extend our hands of cooperation.

(*Interruptions*)

I am not saying that I am blaming the Government. I am saying that we are prepared to extend our hands of cooperatian to sit with the Government, find out a solution so that about whatever the difficulties are there, we can help the Government. Let the Home Minister today say, 'In principle we accept it, we want to implement it. There are certain problems, we will look into them and try to find a solution before the end of this Session'. Why I am saying it is this. Did you not say, The Secretaries Committee will submit its report in three months and then we will take the decision ?' Now, more than four months have passed. Did you not say, 'I will call the Chief Ministers' Conference'? It was called in April. What are the results of that Chief Ministers' Conference ? Therefore, do you accept 27 per cent reservations as recommended by the B.P. Mandal Commission or not ? Are you going to take certain steps in regard to land reforms, in regard to industrial health to those classes or not ? It is not a fight; don't try to differentiate. It is not the cries of backward classe sor upper caste—there is no confrontation. Mr. S.N. Sinha is sitting here. He moved in his own Party a resolution supporting this. Let us do that.

I will only warn Sethiji, if you lose time, you are losing the goodwill of the people. If you lose time you are losing the historical opportunity and you will be responsible for creating the confrontation. On 9th August, 50 Members of this Parliament courted arrest not with the desire to embarrass the Government but to draw attention of the country and the Government. Now certain people have come together and we have also decided if the Government does not accept this before 2nd October, then there will be nation-wide agitation.

Lakhs of people will court arrest. They will go to jail. Do you want that situation to create ? We do not want. I will request you it is not only backward class, minorities have a feeling that they do not have proper representation in police, army and other services and there is resentment in them. Whenever there is communal riot police is called. In them the feeling is that they are not represented, therefore, this law and order authority does not look to them with sympathy. This is not a caste question It is a national question. If you want to create harmony in society, if you want to have the real participated democracy, it is not enough that there will be a few Ministers in the Cabinet, a few Members of Parliament. So, in this important instrument of bureaucracy which is very, very important, there must be proper representation.

With these words I would request the Home Minister to take us into confidence and let this House know what are your problems and difficulties and whether you accept this in principle or not and whether you are going to do something or not. A least acceptance should be made known to the House.

I hope that the Government will take into account the unanimous view of the House and you will take effective immediate steps for acceptance and implementation of B.P. Mandal Commission Report.

SHRI G.M. BANATWALLA (Ponnani): The reservation policy is the minimum practical necessity for the upliftment of those unfortunate who have remained oppressed and discriminated. The Mandal Commission has identified over 3700 backward communities who constitute about 52% of the population. Then there are Schedu led Castes and the Scheduled Tribes. Thus the stark reality of the situation is that three-fourths of the population is in state of the hackward while the elite is keen on preserving its own privileges. This calls for a political will to transform the Indian society as per the provisions of Arts. 15 (4) and 16 (4) of our Constitution.

I rise to urge upon the Government for implementation of the recommendations of the Mandal Commission with an important modification. At present Muslims throughout

Kerala are entitled to reservation consequent to the reports of Kumare Pillai Commission of 1964 and of the Nutoor Commission in 1970. But the Mandal Commission recognises only the Mappillas as backward. The term Mappillas is restricted to only the Muslims of the Malabar area of Kerala. Therefore, I must say that there is no basis for this division and the Muslims throghout the State should continue to be entitled to reservation as at present. Then, the basis on which reservation has been granted to Muslims of Kerala obtain for Muslims in all other States. Reservation should be extended to them on Kerala pattern. The recommendations of the Mandal Commission must be implemented with these modifications.

Before I conclude, I may draw the attention of this House and the Government to a report published on 13th October, 1982 in the Indian Express where we were told that the minorities Commission headed by Shri M.H. Beg had in a report or communication expressed itself against granting of recognition to backward classes as recommended by the Mandal Commission.

This is a matter in which the entire nation must be taken into-confidence. If there is such a report or a communication, it must be placed in all fairness on the Table of the House.

There is the high-powered committee on minorities headed by Dr. Gopal Singh. In June this high-powered committee headed by Dr. Gopal Singh also submitted its final report with respect to minorities, to the Government. We do not know what this high-powered committee has said with respect to reservation. At this critical juncture, when the entire nation is exercised and agitated over the serious question, this report of the high-powered committee on minorities must also be placed on the Table of the House.

Sir, in defence to your restlessness, I conclude by urging upon the Government that the recommendations of the Mandal Commission should be implemented without any delay with modifications as suggested by this humble member.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the Hon Members who have participated in the discussion on the Mandal Commission's report. 20 Hon. Members have participated in the debate on both the sides and I find that almost, barring one or two exceptions, there has been a unanimity that the Mandal Commission's report should be implemented as soon as possible.

I am greately appreciative of the concern expresseed by the Hon. Members about the socio-economic conditions of the backward classes and the suggestions in the context of the Mandal Commission for the improvement of their socio-economic standing in life. The Government fully share the concern and our planning policy has been conditioned by the different kinds of innovations made from time to time keeping this factor in mind.

The House is aware that soon after Independece, certain reservations had been made by the then Madras Government which were invalidated by the Hon. Supreme Court in the Champakum Durai Rajan's case. The Government had at the point of time, under the leadership of Prime Minister Pt. Jawahar Lal Nehru, thought it fit to bring about amendments to Articles 15 and 16 of the Constitution by adding clause 4 to both these Articles.

The House is aware that our party has always been aware of and stood for creation of a society based on social justice. We have always kept in view the feelings, hopes fears and aspirations of the various groups in our pluralistic society and we know that the age-old resignation of masses to their lot is gone for ever. We know that they no longer feel that it is fate that has kept them backward and our effort all along has been to provide the environment and facilities for assisting these sections to move forward.

It is true that after 30 years of Independence, in spite of tremendous strikes made in almost all field, we have not been able to achieve an egalitarian society based on social justice. There are historical reasons for this We are also aware that in spite of our best

efforts, it has not been possible to attain the goals we have set for ourselves in the great adventure of nation building. But I would like to assure this House that our Government is firmally committed to safeguarding the socio-economic interest of all our people and paticularly, all those who are backward from the socicl and educational point of view.

The Government of India had, from time to time, persuaded the State Governments to appoint Commissions and prepare a list of socially and educationally backward classes to provide them weightage in the educational institutions and the employment spheres and the same have borne considerable fruits. Needless to say much still is to be desired in this respect.

The policies pursued by the Government all these years have been guided by the concept of equal opportunity and social justice. Consistent with the concept of Welfare State, Government have been providing all help within the constitutional framework to the socially and educationally backward classes. Government is committed to this concept and would continue to act in a manner that would emancipate these classes from the discriminatory treatment in the society.

While referring to the Commission whose report has been discussed today, I would like to remind the House that although this Commission had been appointed by our predecessor Government, we now desire to continue with this Commission and implement its recommendations. It would have been easy for us when we came to power in 1980 to kind up this Commission whose time expired but, we extended all possible help and cooperation to this Commission with the result that they were able to give the report.

The Commission, after surveying the situation, has made several useful and meaningful recommendations. However, there are some recommendations which deserve to be studied in depth because they have very wide implications as have been mentioned by one or two Hon. Members here.

Moreover, Hon. Members would appreciate that it undoubtedly requires a careful and thorough examination and scrutiny which has been undertaken by the Government. We have consulted the Chief Ministers of all the States. Although there as no unanimity of opinion but most of the State Governments have themselves carried out the reservations in their on States.

Now a Committee of Secretaries has been appointed under the Chairmanship of the Cabinet Secretary. That Committee was to give its report within three months. I am sorry that they have taken more time. But now the Committee has been asked to submit its report within one month.

Yesterday the Prime Minister has appointed a Cabinet Committee to look into this problem and I am sure that.....

SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR : Only to delay.

SHRI P.C. SETHI : There is no question. We have to go into the criteria for declaring a group of people as backward. The Commission did tremendous amount of work to collect the data and it conducted survey on a large scale.

(Interruptions)

However, when this data was analysed, the Commission found that it gave rise to many anomalies which were not compatible with the accepted norms for backwardness with the result that the Commission had to rely more on the lists already announced by the State Governments and on the data provided by the Registrar.

What I am trying to submit is that the criterion for accepting a community to be included among backward classes has to be such that it stands the test of social and educational backwardness.

This is what has been examined in the Committee.

The Cabinet Committee which was been recently appointed only yesterday will go in depth into this matter.

I can assure the Hon. Members that we are desirous and sympathetic towards this problem and we want to implement it. It is difficult for me to pronounce at this stage as to what percentage and in what manner, but, of course, variations are bound to remain because different States have got different reservations and I do not want to go into those details. But, for example, in Andhra Pradesh, the report has included Perikalu Reddy, Teleza Kamma, Vidiki, Niyozi in the lists which are forward communities. Similarly, in Assam, they have included Bhuyan, Chowdhuri, Kayastha (Bengali), Kshattriya and Rajput as backward communities. Similarly, in Karnataka, the Commission has included Lingayat Section and Vokkaliga which cannot be considered backward by any stretch of imagination.

These are the inconsistencies which we will have to go into but I can assure the Hon. Members that we would not take much time to reconcile them.

It would be desirable on the part of Hon. Me bers to postpone their agitational programme from 2nd October to a little more further time.

(Interruptions)

SHRI RAM VILAS PASWAN : I want to seek one clarification. I have already given notice.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Minister, are you going to reply to questions seeking clarifications ?..... He has no time. Hon. Members, he has already replied. We have to take up the Private Members' business at 4.30 p m.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : Now I go to the next item, that is, paper to be laid on the Table. Mr. Harinatha Misra.

———

16.25 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

Rural Landless Employment Guarantee Programme

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : Sir, I beg to lay on the Table a statement (Hindi and English versions) on 'Rural Landless Employment Guarantee programme'.

[*Placed in Library. See No. LT. 6907/83*]

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : It is not a satisfactory reply.

(Interruptions)

SHRI DHANIK LAL MANDAL (Jhanjharpur) : We walk out.

Shri Dhanik Lal Mandal, Shri A. Neelalohithadasan Nadar and some more Hon. Members then left the House.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we take up Private Members' Business. Mr. Shamanna.

———

16.26 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Sixty-Third Report

SHRI T.R. SHAMANNA (Bangalore South) : Sir, I beg to move :

"That this House do agree with the Sixty-third Report of the Committee on Private Members' Bills